सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 16, नई दिल्ली | शनिवार, 01 अप्रैल 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

मन पर नियंत्रण रखना सीखे, क्युकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बिच का काँटा है।

इनसाइड

मियाद पूरी करने वाले पुराने वाहनों को रेट्रोफिटमेंट से मिलेगी नई जिंदगी

दिल्ली। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की मियाद खत्म होने के बाद भी लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं। पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए बुधवार से विशेष अभियान की शुरुआत के साथ ही परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को राहत भी दी है। मियाद पूरी कर चुके पेट्रोल-डीजल वाहनों को रेट्रोफिटमेंट से नई जिंदगी मिलेगी। ई वाहनों के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। ई वाहनों से प्रदूषण नहीं होने की वजह से अधिक दिनों तक इस्तेमाल करने की सुविधा होगी। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर पाबंदी है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (मियाद पूरी करने वाले 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन) के बाद वाहनों का उपयोग करने के लिए रेट्रोफिटमेंट का विकल्प होगा। इसके लिए अधिकृत एजेंसी से ई किट को लगवाना होगा।

1 अप्रैल 2023 से ऑटो इंडस्ट्री में होंगे ये बदलाव

आम जिंदगी में होगा इसका कितना असर

1 अप्रैल 2023 से ऑटो इंडस्ट्री में काफी कुछ बदलाव होने वाला है। चलिए आपको समझाते हैं इसके बारे में विस्तार से ताकि आप इन बदलावों के बारे में बढ़िया से समझ सकें।

संजय बाटला

नई दिल्ली। एक अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष चालू होने वाला है। जिसमें आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगें। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पर भी देखने को मिलेगा। कल से कुल चार नियम में बदलाव होने वाले हैं, चलिए आपको एक -एक करके बताते हैं बदलाव के बारे में।

BS6 फेज 2 होगा लागू

नए नियम और शर्तों को पूरा करने के लिए सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी पेट्रोल -डीजल गाड़ियों में अपडेट करना होगा। इस अपडेट के तहत RDE डायग्नोस्टिक डिवाइस और प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टर शामिल होंगे। कुल मिलाकर कंपनियों को मौजूदा असेंबली को बदलने की जरूरत है। इसके कारण डेवलप कॉस्ट बढ़ेगी। इसका सीधा असर वाहनों की कीमत पर पड़ेगा। हम बात कर रहें है...BS6 फेज 2 की आपको बता दें, BS6 फेज़ 2 में रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म लागू किया गया है। BS6 फेज 2 में रियल ड्राइविंग एमिशन यानी RDE लागू होगा जिसके वजह से गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए, रियल लाइफ कंडीशन में भी एमिशन के कायदों पर खरा उतरना होगा। गाड़ियों की RDE टेस्टिंग सड़कों पर होगी और टेस्ट में देखा जाएगा कि गाड़ी के धुएं में पोल्यूटेंट्स तय सीमा से अधिक तो नहीं निकल रही है। वहीं नई गाड़ियों को सड़क पर उतरने के लिए RDE सर्टिफिकेशन लेना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही गाड़ियों को पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट सिस्टम भी लैस किया जाएगा। जिससे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की जांच रियल टाइम में होती रहे।

17 गाड़ियां होगी बंद

बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत ही सरकार 1 अप्रैल को नया उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने वाली है। नए मानदंडों को लागू करने के बाद कई गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें, ये वाहन निर्माता कंपनियों के साथ -साथ ग्राहकों के लिए भी बुरी खबर है। क्योंकि, ये पुरानी गाड़ियों की कीमत कम थी, वहीं नए मानक के साथ अगर ये गाड़ियां फिर से लॉन्च होती है तो इनकी कीमत में ये बढ़ोतरी होगी।

चलिए आपको बताते हैं कौन -कौन सी गाड़ियां बंद होने वाली है। टाटा अल्ट्रोज डीजल, महिंद्रा मराजो, महिंद्रा अल्टुरस जी, महिंद्रा केयूवी100, स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा सुपर्ब, होंडा सिटी 4th Gen, होंडा सिटी 5th Gen डीजल, होंडा अमेज डीजल, होंडा जैज, होंडा डब्ल्यूआर-वी, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल, हुंडई i20 डीजल, हुंडई वरना डीजल, रेनो क्विड 800, निसान किक्स,

कीमत में होगी बढ़ोतरी

1 अप्रैल से BS-6 के दूसरे चरण के नियम लागू हो जाएंगा जिसके कारण वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। मारुति भी अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी करने वाली है, लेकिन वो कार के हर मॉडल के अनुसार होगी। इसके साथ ही होंडा कार्स (Honda Cars), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) सहित कई कार बनाने कंपनियां कीमत में बढ़ोतरी करेंगी। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 1 अप्रैल से 5% तक बढ़ाने का ऐलान किया था, वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने भी 1 अप्रैल 2023 से अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए होगा बदलाव

सेकेंड हैंड कार को लेकर नियम में बदलाव होने वाला है। सेकेंड हैंड कार खरीदने और बेचने वाले डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया गया है जिसके तहत डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट देना होगा। जिसमें डीलरों को मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण/फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय III में संशोधन किया है।

रातभर हुई बारिश से दिल्ली में धंसी सड़क

डीटीसी बस फंसी; हो सकता था बड़ा हादसा

नई दिल्ली। प्रेस एन्क्लेव रोड पर हौज रानी रेड लाइट के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंस जाने से डीटीसी की बस फंस गई। गुरुवार रात भर हुई बारिश से प्रेस एन्क्लेव रोड पर हौज रानी रेड लाइट के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंस जाने से डीटीसी की बस फंस गई। साकेत कोर्ट से पीटीएस, मालवीय नगर की ओर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इस मार्ग से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी बना हुआ। इसके कारण शुक्रवार को भी तेज बारिश होने का अनुमान है। गुरुवार को दिन में तेज धूप निकली हुई थी। इस कारण से अधिकतम

तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर तीन बजे के बाद आसमान में काले बादल छा गए। लगभग चार बजे तेज हवा के साथ तेज बारिश होने लगी। बारिश का यह दौर सात बजे तक जारी रहा।

सफदरजंग में बारिश के साथ 36 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली। जबकि पालम में 50 किलोमीटर प्रतिघंटे रफ्तार की हवा के साथ 1.1 मिमी बारिश दर्ज हुई। रिज में 4.5 मिमी बारिश दर्ज हुई।

विभाग ने शुक्रवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ हवा चलने की संभावना है। इस कारण से तापमान 27 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तीन अप्रैल से तापमान बढ़ना शुरू होगा और पांच अप्रैल आते-आते तापमान 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बीते बुधवार को भी शाम को मौसम का मिजाज बदल गया था और कुछ इलाकों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने तीन दिन तक बारिश की भविष्यवाणी की थी। इसके अनुसार अभी शुक्रवार और शनिवार को भी बदरा बरसेंगे।

दिल्ली की सार्वजनिक सवारी सेवा कितनी सुखद और सुरक्षित, जानें

संजय बाटला

नई दिल्ली । दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा प्रदान करने वाली बसों का हाल देखने वाला दिल्ली परिवहन विभाग/दिल्ली परिवहन निगम/दिल्ली सरकार और कलस्टर कंपनियों द्वारा चालित बसों का मैनेजमेंट संभालने वाली कम्पनी डिम्ट्स में से कोई भी नहीं, आख़िर क्यों ?

जनता को सुरक्षित सार्वजनिक सवारी सेवा प्रदान करवाना राज्य सरकार और परिवहन विभाग का मुख्य दायित्व है पर दिल्ली की जनता को विज्ञापनो और फाइलों में तो सुरक्षित सवारी सेवा प्रदान करने का दावा सभी राज्यों से अधिक है पर सच उसके बिलकुल विपरीत है !!!

सब जानने/ देखने के बाद भी परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री (चैयरमैन डीटीसी), एमडी डीटीसी और वाइस प्रेसिडेंट डिम्ट्स अपने आंख कान बंद कर के बैठे हैं, आख़िर क्यों ???*

दिल्ली में चलती बसों के खराब होकर कही भी खड़ा हो जाना,

दिल्ली में चलती बसों से पुर्जे टूट कर गिर जाना,

दिल्ली में चलती बसों के टायर निकल कर दूर जा कर गिर जाना

दिल्ली में चलती बसों में आग लग जाना और

जरा सी भी बरसात में बसों के अन्दर झरने की तरह पानी बरसना

दिल्ली की जनता को दिल्ली परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री, एमडी डीटीसी के शब्दों के अनुसार सुखद अहसास और विश्व की सबसे सुरक्षित सार्वजनिक सेवा उपल्ब्ध करवाना है।*

अब आप ही बताइए क्या सही और क्या सच ?

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

अब फुटकर सवारी नहीं बैठा पाएंगे विक्रम, गैराज से ही होगी बुकिंग, शर्तो के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

विक्रम संचालक काउंटर बनाकर बुकिंग करें या परमिट में घोषित किए गए गैराज में विक्रम खड़ा कर बुकिंग के बाद सवारियां ले जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्किंग बनाकर भी विक्रम संचालक बुकिंग कर सकते हैं।

देहरादून। हाईकोर्ट से दून संभाग के विक्रम चालकों को फिलहाल बेशक राहत मिल गई हो, लेकिन परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि विक्रम संचालकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करना होगा। परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि विक्रम संचालक काउंटर बनाकर बुकिंग करें या परमिट में घोषित किए गए गैराज में विक्रम खड़ा कर बुकिंग के बाद सवारियां ले जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्किंग बनाकर भी विक्रम संचालक बुकिंग कर सकते हैं। परिवहन विभाग आईएसबीटी के पास थोड़ा स्थान विक्रमों को देने पर विचार कर रहा है। कहा कि परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का चालान, परमिट सस्पेंड और निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

आरटीओ के इस आदेश के बाद विक्रम संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। विक्रम जनकल्याण सेवा समिति के सचिव संजय अरोड़ा का कहना है कि विक्रम में बुकिंग कर सवारी बिठाना संभव नहीं है। शहर में विक्रम के लिए कोई स्टैंड नहीं है। कहा कि वह टैक्स स्टेज कैरिज का देते हैं, इंश्योरेंस भी स्टेज कैरिज में जमा होता है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की शर्तें उन पर क्यों थोपी जा रही हैं।

दरअसल, दून के सभी विक्रमों का परमिट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में है। इसके अनुसार टैंपो स्टैंड से बुकिंग करने के बाद ही विक्रम सवारी बिठा सकते हैं, लेकिन अब तक विक्रम संचालक स्टेज कैरिज में फुटकर सवारियां बिठाते आ रहे थे। फुटकर सवारी बिठाने की छूट न मिलने से विक्रम संचालकों के लिए मुसीबत हो सकती है। वहीं, दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाईकोर्ट के निर्णय

पर खुशी जताई है। बैठक में यूनियन के सदस्यों ने अध्यक्ष पंकज अरोड़ा का माला पहनाकर स्वागत किया।

जब दस साल पुराने विक्रमों को हटाकर उनकी जगह नए टाटा मैजिक लगाने का फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। यह भी तय हुआ कि एक अप्रैल से विक्रम संचालक अपने कांट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करेंगे। जबकि, स्टेज कैरिज में मैजिक संचालक सवारी बिठाएंगे। एक अप्रैल से दस साल पुराने विक्रमों को चलन से बाहर किया जाना था। इसमें हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। इससे विक्रम संचालक राहत मिली, लेकिन फुटकर सवारी नहीं बिठा पाने की बाध्यता उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगी।

देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन का कहना है कि 12 सवारियों से नीचे की क्षमता वाली गाड़ियों को स्टेज कैरिज का परमिट नहीं दिया जा सकता। 13 प्लस 1 की क्षमाता वाली गाड़ियों को यह परमिट दिया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है। इसके मुताबिक विक्रम और टाटा मैजिक को स्टेज कैरिज का परमिट नहीं दिया जा सकता। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार स्टेज कैरिज परमिट धारक वाहन एक स्थान से अपनी यात्रा शुरू करता है। अंतिम गंतव्य बिंदु तक इसमें कई स्टापेज हो सकते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में बुकिंग कर एक स्थान से निर्धारित गंतव्य तक सवारी को ले जाया जाता है। इसमें बीच में वाहन को नहीं रोका जाता।

नागरिक उड्डयन विभाग ने भेजी 99 करोड़ की राशि, इंटरचेज और 8 लेन के हाइवे को होगा निर्माण

एयरपोर्ट से जल्द जुड़ेगा दिल्ली-मुंबई व यमुना एक्सप्रेसवे, 99 करोड़ मिले

800 मीटर लंबा होगा 8 लेन का हाईवे

परिवहन विशेष न्यूज

जेवर। नोएडा एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने 122 करोड़ की अनुमानित लागत से 99 करोड़ रुपये की राशि जिलाधिकारी के खाते में भेज दी है। जिससे अब जल्द यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज और इंटरचेंज से एयरपोर्ट तक 8 लेन के 800 मीटर हाईवे का निर्माण शुरू किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संशेधित बजट को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने इंटरचेज की लागत का 50 प्रतिशत और 800 मीटर हाईवे की लागत का 100 प्रतिशत धनराशि जारी की है।

जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए फरीदाबाद, बल्लभगढ़ बाइपास केएमपी लिंक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से हाल ही में संशोधित बजट का प्रस्ताव मांगा गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरचेज के निर्माण में 145 करोड़ रुपये का अनुमान बताया। वहीं इंटरचेज से एयरपोर्ट तक 800 मीटर 8 लेन के हाइवे व सर्विस रोड बनाने में लगभग 50 करोड़ की लागत का आंकलन किया था।

नागरिक उड्डयन विभाग ने राज्यपाल की अनुमति के बाद राशि जारी कर दी है। जिलाधिकारी इस धनराशि को आवश्यकता अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे जिससे हाईवे के लिए जमीन लेने और अन्य निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे। संवाद

इंटरचेंज तक जमीन खरीदने को प्रदेश सरकार पहले ही दे चुकी है 361 करोड़ की मंजूरी

एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बल्लभगढ़ से जोड़ने वाले 31 किमी लंबे प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए 66.73 हेक्टेयर जमीन की खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके अधिग्रहण के लिए लगभग 260 करोड़ का खर्च होंगे। साथ ही बल्लभगढ़ से एयरपोर्ट को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर प्रस्तावित इंटरचेंज के लिए 19 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए लगभग 76 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट के लिए बनने वाले इंटरचेंज से एयरपोर्ट की चहारदीवारी को जोड़ने के लिए करीब 800 मीटर लिंक रोड ;एक्सप्रेसवे के लिए 4.42 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिसके लिए अनुमानित 361 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण को प्रदेश सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

एनएचएआई जारी कर चुका है 2114 करोड़

भारतमाला परियोजना के तहत एनएचएआई 1350 किमी लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे करीब कबीब बनकर तैयार हो चुका है। आठ लेन के इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई को जोड़ा जा रहा है। जिसे बाद में इसे 12 लेन का करने की भी योजना। पिछले काफी समय से इस एक्सप्रेस से नोएडा एयरपोर्ट का जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएनडी फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाइपास केएमपी लिंक से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए 2114.67 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी थी।

लखनऊ व दिल्ली एक घंटे पहले पहुंचाएगी राजधानी बस

हाथरस। हाथरस से राजधानी बस सेवा में लखनऊ व दिल्ली के लिए सफर करने वाले यात्रियों को 1.43 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। राजधानी बस सेवा में यात्री सुविधाओं के लिए पैनिक बटन लगाया गया है। यह बस लखनऊ व दिल्ली सामान्य बसों से करीब एक घंटा पहले पहुंचेगी। हाथरस डिपो में हाल में चार बसें आई है। जिन पर राजधानी बस सेवा का लोगो लगा है। दो बसें लखनऊ व दो बसें दिल्ली के लिए संचालित होती हैं। पहले लोग साधारण बसों से राजधानी का सफर करते थे। राजधानी बस सेवा में प्रत्येक सीट पर पैनिक बटन लगा हुआ है। यह बस नियत स्थल पर ही रुकेगी। ये बसें अन्य बसों से एक से डेढ़ घंटे पहले पहंचेगी। आरएम सतेंद्र वर्मा का कहना है कि राजधानी बस सेवा में दस प्रतिशत किराया अतिरिक्त है। राजधानी बस सेवा अन्य बसों से पहले पहुंचाएगी।

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.
-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.
-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.

-ऐसे बच्चे अधिक एग्रेसिव और हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं.

आप भी पुरानी बातों को लेकर रहती हैं बेचैन? इन 4 तरीकों से जिंदगी बनाएं खुशहाल, मिलेगी हर मंजिल

अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर बने, तो अपने पुराने निर्णयों को स्वीकारना शुरू करें और उन्हें जीवन में बड़ी सीख की तरह देखें. ऐसा करने से आप उन्हें जीवनभर बोझ बनाकर ढोने से बच जाएंगी और आगे बेहतर तरीके से जी सकेंगी.

अगर आपको इस बात का पछतावा रहता है कि आपके कुछ गलत निर्णयों की वजह से आपकी जिंदगी आज बुरे हालातों से गुजर रही है तो ऐसा सोचने वाली अकेली आप नहीं हैं. खासतौर पर अगर आपने अपने किसी निर्णय की वजह से कुछ बहुत ही खास चीज को खो दिया है या जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो ये पछतावा आपको जीवनभर के लिए अवसाद में जीने को मजबूर कर सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप पुराने पछतावों से किस तरह खुद को उबार सकती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं.

पुराने पछतावों से खुद को ऐसे उबारें

लिस्ट बनाएं

जीक्यूइंडियाके मुताबिक, पछतावों से खुद को उबारने के लिए उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपने अपनी गलतियों से सीखी है. दरअसल गलत निर्णय जीवन में सीख की तरह होते हैं. अगर आप इन्हें सकारात्मक तरीके से स्वीकारें तो ये आपको जीवन में आगे होने वाली गलतियों से आपको बचा सकते हैं. इस तरह आप खुद की गलतियों को यादा करें और उनसे सीख लें. इस तरह आप बेहतर डिसीजन मेकर बन पाएंगी.

खुद को करें माफ

गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने और खुद का सजा देने की बजाय बेहतर होगा कि आप खुद को माफ करें. ऐसा करने से आप चीजों को भूलकर आगे खुशहाल रहेंगी और आगे जजमेंटल होकर निर्णय नहीं लेंगी.

अपने पछतावों को लिखें

आप अपने अंदर पल रही निगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए अपने पछतावों को एक जगह लिखें और विचार करें कि क्या ऐसा ना होने पर आपकी जिंदगी सच में बदली होती ! यकीन मानिए, आपके सवालों का जवाब आपको जैसे ही मिल जाएगा आप पछतावों से छुटकारा पा जाएंगी.

इस विषय पर करें बात

अगर आपको यह लग रहा है कि आप अपने पछतावों के तले दबा हुआ और घुटन सा महसूस कर रही हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी अपने विश्वसनीय से इस विषय पर बात करें. कई बार अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेने और खुलकर बात कर लेने से भी बेहतर महसूस होता है.

बिज़ी लाइफ में इन तरीकों से महिलाएं निकालें खुद के लिए समय

महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है. महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है.

कामकाजी महिलाओं (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में कुछ तरीकों की मदद से वे अपना काम आसान कर सकती हैं और अपने लिए समय बचा सकती हैं ताकि वे अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें.

आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टास्क हो गया है. इस समस्या से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं और जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए तो खुद के लिए समय निकालना नामुमकिन है. वर्किंग विमेन (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. जिसे पूरा करते-करते वे ना तो चैन की सांस ले पाती हैं और ना ही अपनी नींद पूरी कर पाती हैं. ऐसे में स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ता है.
इस समस्या को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

चाबियों पर लगाएं अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश

अक्सर जब किसी काम को जल्दी पूरा करना हो या हम जब जल्दी में होते हैं तभी छोटी-छोटी चीजों की वजह से देर होने लगती. ऐसे में आप अपने घर की कई चाबियों को अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश से रंग सकते हैं. इससे आपको पर्टिकुलर लॉक के लिए सारी चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं.

कंघी करते समय रखें ध्यान

ऑफिस जाते समय जल्दी-जल्दी में बालों को सुलझाने में महिलाएं बालों के साथ खींचतान करने लगते हैं. जिससे बाल अधिक टूटते हैं और नीचे गिर कर काम बढ़ा देते हैं. इससे बचने के लिए अपने हेयर ब्रश में बटर पेपर लगाकर कंघी करें. इससे बाल जल्दी सुलझ जाएंगे और नीचे भी नहीं गिरेंगे.

हेयर स्ट्रेटनर से प्रेस करें

सुबह के समय जल्दी रहे तो आप प्रेस के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके कपड़े जल्दी प्नेस होंगे और आपका समय बच जाएगा.

कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये ऐप्स

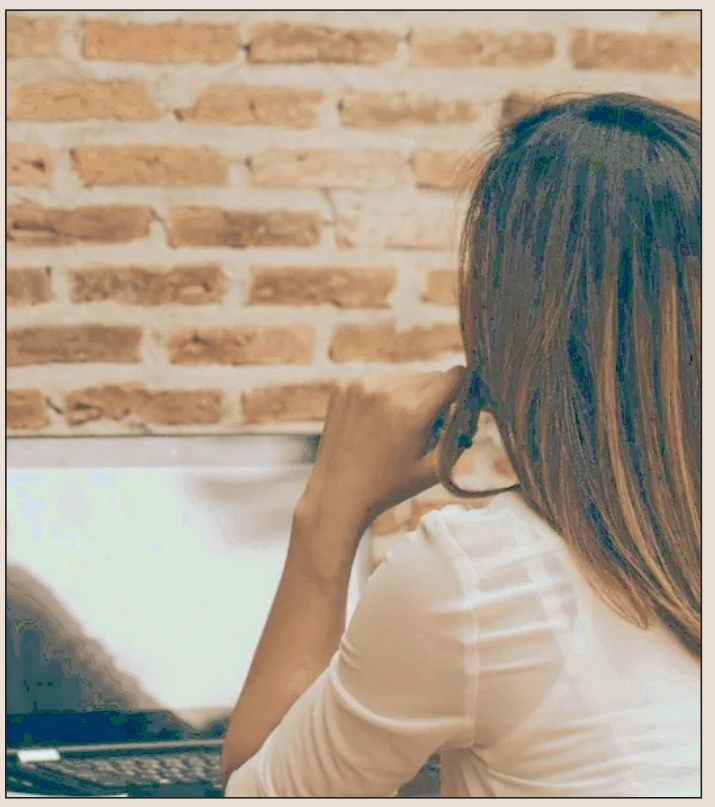

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है.

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज में ऐप्स की मदद से आगे बढ़ रही हैं और पैसे भी कमा पा रही हैं. सबसे खास बात यह है कुछ प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.
अगर आप किसी कारणवश अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई हैं, या आपने केवल 10वीं या 12वीं तक की ही पढ़ाई की है और आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, इस अब आपको ऐसा मौका मिल सकता है. क्योंकि देश में कई ऐसे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जो खासरकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. इन ऐप्स के इस्तेमाल से महिलाओं ने 2021 में तरक्की के कई रास्ते खोले और अब 2022 में भी ये उनकी मदद कर रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर (**Delhi-NCR**), मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज में बहुचर्चित 'अपना (**apna**)' ऐप ने महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाई है. बीते साल करीब लाखों महिलाओं ने इसका इस्तेमाल कर नौकरी पाई. सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.
इन ऐप्स पर सिर्फ अपनी जानकारी डालने के बाद उनके पास जरूरत के हिसाब से नौकरी पाने के ऑफर आते रहते हैं. 12वीं पास महिलाओं ने सबसे ज्यादा टेलीकॉलर, बीपीओ, बैक ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस, टीचर, अकाउंटेंट, एडमिन ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए आवेदन किया है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत प्लेटफॉर्म

इसी तरह खास महिलाओं के लिए चलाई जा रही सोशल नेटवर्किंग साइट 'शीरोज (**Sheroes**)' भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई है. यहां हर उम्र वर्ग की महिलाएं, ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जुड़ती हैं. वह नौकरी के अवसर भी तलाशती है, साथ ही अगर वह अपने लेवल पर किसी तरह का बिजनेस कर रही हैं, तो उसे प्रमोट भी करती हैं. बिजनेस वुमेन इसके सहारे अपना नेटवर्क मजबूत कर रही हैं. इस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई.

जो महिलाएं मां नहीं बन पातीं, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा: नई रिसर्च

महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है. (सांकेतिक तस्वीर) महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है.

ब्रिटेन में हुई रिसर्च से पता चला है कि जिन औरतों में बांझपन (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका 16 फीसदी तक ज्यादा होती है. महिला को गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ में परेशानी हो तो बाद के सालों में दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है.
प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी
प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी
लंदन: एक नए शोध से पता चला है कि महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने (infertility) की समस्या का संबंध दिल की बीमारी से भी होता है. ब्रिटेन में हुई रिसर्च के बाद दावा किया गया है कि जिन औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका बाकी महिलाओं से 16 फीसदी तक ज्यादा होती है.
अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल में छपे इस शोध में कहा गया है कि महिलाओं के प्रजनन इतिहास से काफी हद तक पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है. महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है. इस शोध के दौरान दो तरह के हृदयाघात यानी हार्ट फेल होने की स्टडी की गई. पहला preserved ejection fraction के साथ हार्ट अटैक (HFpEF) जिसमें दिल की मांसपेशियां खून पंप करने के बाद पूरी तरह फैल नहीं पातीं. दूसरा हार्ट फेल्योर विद reduced ejection fraction (HFrEF). इसमें बाएं वेंट्रीकल यानी दिल के निचले भाग के कोष से हर धड़कन के बाद जितना खून शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता. महिलाओं में हार्ट फेल के ज्यादातर मामले HFpEF के ही होते हैं. शोध करने वाली टीम की लीडर और मैसाचूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ ने बताया कि रिसर्च के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि महिलाओं में थायरायड या जल्दी मेनॉपॉज़ जैसी समस्याओं का भी क्या प्रजनन क्षमता और दिल की बीमारी से कोई लेना-देना होता है या नहीं. लेकिन इस धारणा को लेकर किसी तरह के पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं.
शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक ये तो पता था कि जिन महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की समस्या होती है, उनमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं. लेकिन बांझपन का दिल की बीमारी पर असर को लेकर कोई पुख्ता स्टडी नहीं हुई थी. आमतौर पर दिल की बीमारी को 50 साल के बाद की समस्या माना जाता है, जबकि बांझपन उम्र के 20वें, 30वें या 40वें पड़ाव पर आने वाली दिक्कत है. इसलिए इन दोनों के संबंध पर गौर नहीं किया जाता. अब महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की क्षमता का कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य का ध्यान तो रखा ही जा सकता है ताकि उन्हें दिल की बीमारियों से बचाया जा सके.

जेल में ही कुछ और दिन काटेंगे मनीष सिसोदिया

राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आबकारी नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है।विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया।

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया। अदालत ने सीबीआई और सिसोदिया पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद 24 मार्च को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया वर्तमान में सीबीआई के भ्रष्टाचार और ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

सीबीआई ने किया पुरजोर विरोध

सिसोदिया ने अपने स्वास्थ्य और पत्नी के देखभाल समेत अन्य आधार पर जमानत दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया था। वहीं, जांच एजेंसी ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया को अगर जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर देंगे और वह सुबूतों को नष्ट करने का निरंतर अभ्यास जारी रखेंगे।

ये है आरोप

बता दें कि सिसोदिया पर आरोप लगे है कि उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाने के लिए बार-बार अधिकारी बदले थे, बल्कि मोबाइल फोन और विभिन्न फाइलों को भी नष्ट कर दिया था।

रोहिणी कोर्ट की चौथी मंजिल से एक शख्स ने लगाई छलांग, हालत नाजुक

शुक्रवार को दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट की चौथी मंजिल से एक व्यक्ति ने छलांग लाग कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। शख्स को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। चौथी मंजिल से छलांग लगाने के बाद व्यक्ति की हलाल नाजुक बनी हुई और उसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर कोर्ट परिसर से छलांग लगने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में लग रहा है। अभी व्यक्ति के आत्महत्या के करने की असली वजह का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।

इनसाइड

आईपी कॉलेज की छात्राओं ने लहराए प्लेकार्ड, प्रिंसिपल से मांगा इस्तीफा

दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में एक समारोह के दौरान कथित उत्पीड़न की घटना के बाद शुक्रवार को कई छात्रों ने प्रिंसिपल पूनम कुमारिया के इस्तीफे की मांग की है। मंगलवार को अज्ञात लोगों ने कॉलेज में समारोह के दौरान कथित रूप से उत्पात मचाया था।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में एक समारोह के दौरान कथित उत्पीड़न की घटना के बाद शुक्रवार को कई छात्रों ने प्रिंसिपल पूनम कुमरिया के इस्तीफे की मांग की है। मंगलवार को अज्ञात लोगों ने कॉलेज में समारोह के दौरान कथित रूप से उत्पात मचाया था। बाहर से आए लोगों ने कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ की थी।

'पूनम कुमरिया इस्तीफा दो'

'पूनम कुमरिया इतिफा दो' के नारे के बीच परिसर में सभी महिला कॉलेज के छात्रों ने एक मार्च आयोजित किया। इस घटना के विरोध में करीब 200 लोग जमा हुए। एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, 'हम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई, प्रिंसिपल के इस्तीफे और जीएससीएएसएच (यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदी समिति) की स्थापना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, जिन्होंने बुधवार को विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए छात्रों को कथित रूप से परेशान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को कथित घटना के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 337 (किसी के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 188 (लोक सेवक द्वारा कानूनन लागू आदेश का उल्लंघन) के तहत प्राथमिकी दर्ज की और सात लोगों को गिरफ्तार किया।

दोस्त को मारने के लिए सिवान से बुलाए शूटर, प्रॉपर्टी डीलर को ऑफिस में मारी थी गोली; 5 गिरफ्तार

कारोबारी साझीदार से अनबन होने पर एक शख्स ने उनकी हत्या करने की ठान ली। इसके लिए उसने बिहार के सिवान से शूटरों को दिल्ली बुलाया। शूटर ने गोली चलाई लेकिन जिन पर गोली चलाई वह बाल-बाल बच गए।

नई दिल्ली। कारोबारी साझीदार से अनबन होने पर एक शख्स ने उनकी हत्या करने की ठान ली। इसके लिए उसने बिहार के सिवान से शूटरों को दिल्ली बुलाया। शूटर ने गोली चलाई लेकिन जिन पर गोली चलाई, वह बाल-बाल बच गए। द्वारका जिला पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस के हत्थे न सिर्फ आरोपी चढ़े बल्कि सिवान में अवैध हथियार के काले धंधे का भी पता लगा लिया।

इस मामले में अभी तक पांच आरोपियों शिव कुमार, सतेंद्र, राहुल, अंकुर, बबलू की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके कब्जे और निशानदेही पर 8 पिस्टल, 11 कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। छानबीन अभी जारी है।

15 मार्च को मारी गोली

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि 15 मार्च को द्वारका नॉर्थ थाना क्षेत्र में बिजेंद्र नामक प्रॉपर्टी कारोबारी पर गोली चलने की सूचना मिली। हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम को इस मामले में आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार

टीम ने तकनीकी छानबीन व सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं एकत्रित करनी शुरू कीं। मामले में पुलिस ने सतेंद्र, राहुल, अंकुर को दबोच लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से दो पिस्टल पुलिस ने बरामद हुईं। एक मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से बरामद की गई। पूछताछ में तीनों ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता शिव कुमार है। इसके बाद शिव कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सामने आया सिवान कनेक्शन

शिव कुमार ने पूछताछ में बताया कि बिजेंद्र और वह पहले दोस्त थे। किसी बात दोनों में अनबन हुई। इसके बाद शिव कुमार ने बिजेंद्र से बदला लेने का फैसला किया। इसे रास्ते से हटाने का इरादा करने के बाद वह सिवान गया ताकि वहां से शूटरों का इंतजाम किया जा सके। इस कार्य में सतेंद्र ने उसकी मदद की। वहां से राहुल व अंकुर नामक दो शूटरों को दिल्ली बुलाया गया।

पूछताछ के बाद सिवान में की छापेमारी

दोनों को हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए गए। यहां बिजेंद्र को उनके कार्यालय में इन्होंने गोली मारी और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। जब पुलिस ने यह पूछा कि दोनों पिस्टल कहां से खरीदे तब उन्होंने कहा कि ये पिस्टल सिवान स्थित पाली गन हाउस से खरीदे हैं। इसके बाद टीम ने सिवान में छापेमारी की। वहां पुलिस ने पाली गन हाउस के संचालक बबलू शर्मा को गिरफ्तार किया।

गन हाउस में पुलिस को छह अवैध पिस्टल मिले। बबलू से पूछताछ में पता चला कि उसे पूर्व में सिवान मे दर्ज एक प्राथमिकी में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को यह भी पता चला कि बबलू गन हाउस की आड़ में अवैध हथियार का काला धंधा कर रहा था। अवैध हथियार वह मध्यप्रदेश के भिंड से खरीदता था। पुलिस को छानबीन में पता चला कि बबलू जम्मू कश्मीर के अपराधियों के भी संपर्क में है जो आतंकियों के संपर्क में हैं।

25 हजार का जुर्माना लगने पर बोले केजरीवाल- PM कितना पढ़े हैं? देश को ये जानने का है अधिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CEC) के आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी और पीएमओ से डिग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CEC) के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी और पीएमओ से डिग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ₹क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।₹

सीईसी के आदेश को किया रद्द

बता दें कि मुख्य सूचना आयोग (CEC) ने पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (PIO) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल कर डिग्री दिखाने की मांग की थी।

डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं

जिस पर 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

कई बार उठा चुके हैं डिग्री वाला मुद्दा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कई बार उनकी डिग्री को सार्वजनिक रूप से दिखाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधानसभा में पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं।

फिर बिगड़े राजेंद्र पाल गौतम के बोल, श्रीरामचरित मानस पर दिया विवादित बयान

नई दिल्ली। उन्होंने कहा कि जिस ग्रंथ को भारत में कुछ लोग पूजते हैं वो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा और उस पर शोर शराबा भी हुआ है। गौतम ने कहा यह ग्रंथ कहता है कि 'ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी'। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने बगैर नाम लिए तुलसीकृत श्रीरामचरित मानस का बहिष्कार करने की मांग कर दी। विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने श्रीराम चरित मानस की एक चौपाई पर सवाल उठाया। इसे हटाने की मांग करते हुए कहा कि इसमें महिलाओं के उत्पीड़न को प्रश्रय दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस ग्रंथ को भारत में कुछ लोग पूजते हैं, वो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा और उस पर शोर शराबा भी हुआ है।

गौतम ने कहा, यह ग्रंथ कहता है कि 'ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी'। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रंथ की पूजा करना, जो ढोल गंवार क्षुद्र पशु और नारी को एक श्रेणी में रखकर मारने पीटने की बात करता है। उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ इंसान को इंसान ना मानने की बात करता है, ऐसे ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसी बातों को ग्रंथ से अविलंब हटाया जाना चाहिए। गौतम ने कहा कि यह महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला है।

शुक्रवार सुबह छह बजे रोजा शुरू करने से पूर्व सहरी खाकर पूरा परिवार सो गया।

रमजान की खुशी मातम में बदली, मच्छर मारने वाला कॉइल जला... और बुझ गया घर का चिराग

शुक्रवार सुबह छह बजे रोजा शुरू करने से पूर्व सहरी खाकर पूरा परिवार सो गया। इसके बाद अचानक घर में आग लगी और पूरे घर में धुंआ फैल गया। परिवार से सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन मासूम हमजा धुएं की घुटन सह नहीं पाया।

नई दिल्ली। शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद इलाके में रमजान के दिनों हुए दर्दनाक हादसे में दम घुटने से एक घर का चिराग बुझ गया। इस हादसे में दो वर्ष की आयु के बच्चे हमजा की मृत्यु हो गई। हादसे और बच्चे की मृत्यु से परिवार और पड़ोस में मातम छाया हुआ है।

शुक्रवार सुबह छह बजे रोजा शुरू करने से पूर्व सहरी खाकर पूरा परिवार सो गया। इसके बाद अचानक घर में आग लगी और पूरे घर में धुंआ फैल गया। परिवार से सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मासूम हमजा धुएं की घुटन सह नहीं पाया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।

पीड़ित नाजमीन ने बताया कि सहरी खाकर वह सो गए थे। करीब साढ़े सात बजे पति अजमत ने उन्हें नींद से उठाया तो उन्होंने देखा पूरे घर में धुंआ छाया हुआ था। इसके बाद उनके पति ने उन्हें उठाया और बेटी सोनी, माहिरा और बेटे फरहान को भी उठाकर बाहर ले गए, लेकिन वह अपने सबसे छोटे बेटे हमजा को उठाना भूल गए। जब तक उसे दोबारा लेने गए उसकी मृत्यु दम घुटने से मृत्यु हो चुकी थी। उनकी बेटी सोनी भी आग में झुलस गई थी, उसका जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अकबर ने हिम्मत दिखाकर बचाई परिवारवालों-किराएदारों की जान

पीड़ित परिवार 100 गज के पांच मंजिला घर में रहता है। जिसमें हर तल पर तीन कमरे हैं। आग भूतल पर लगी थी। पीड़ित अकबर ने बताया कि यह घर उनके पिता हमजद अली का था। पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब यह घर उनके छोटे भाई अजगर के नाम पर है। उनके छह भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े वह खुद हैं। दो भाई अन्ना और वसीम जेल में हैं। भाई अजगर की परचून की दुकान है और अजमत गाड़ी चलता है।

भाई के परिवार के अलावा चार कमरों में किराएदार रह रहे थे। हादसे के समय वह भूतल पर पत्नी शबाना और बच्चों के साथ सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में भाई अन्ना की पत्नी सुमाइला और डेढ़ साल का बेटा अरम सो रहा था। अचानक से सुमाइला आई और उसने बताया कि उसके कमरे में आग गई। उन्होंने सभी लोगों को सुरक्षित घर के बाहर निकाला और खुद बाल्टी भरकर पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग और बढ़ने लगी।

इसके बाद पूरे घर में धुआं उठने लगा। धुंआ फैलने पर पहली मंजिल पर जाकर भाई अजमत को भी उठाया। अजमत के दो बच्चे माहिरा और फरहान को उठाकर बाहर भी ले गए। उन्हें धुएं के कारण भतीजा हमजा नजर नहीं आया, वरना वह उसे भी बचा लेते। तभी ऊपर से किराएदार और परिवार के बाकि सदस्य भी आ गए, धुएं के कारण किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अजमत के साथ मिलकर एक एक करके सभी को बाहर निकलवाया। इसमें कुछ पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की।

छत से कूदकर बचाई जान

तीन मृतक और एक घायल सहित आठ किराएदार पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। पीड़ित किराएदार मकबूल ने बताया कि वह सभी दिल्ली रोजगार की तलाश में आए और यहां ई रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका चला रहे थे। हादसे के समय वह लोग तीसरे तल पर सो रहे थे। आग का धुंआ ऊपर पहुंचने पर वह जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागे और छत से पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। किराएदार जाइरूल नीचे के रास्ते चला गया, जो आग में झुलस गया। जिसका जीटीबी अस्पताल में ईलाज चल रहा था।

नोएडा: राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर शुक्रवार रात से महंगी होगी यात्रा, टोल प्रबंधन ने जारी की सूचना

शुक्रवार की मध्य रात से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा महंगी होने जा रही है। दादरी से गुजरने वाले एनएच 34 पर भी नई टोल दरें प्रभावी होंगी। टोल प्रबंधन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। वहीं हल्के वाणिज्यक वाहनों के लिए यह दर 220 रुपये है।

नोएडा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज आधी रात से यात्रा महंगी हो जाएगी। टोल शुल्क की नई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू होंगी। एनएच 34 के लुहारली टोल प्लाजा पर नई दरों के अनुसार टोल वसूली की जाएगी।

शनिवार से नए वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए वित्त वर्ष में टोल शुल्क की दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि शुक्रवार आधी रात से प्रभावी हो जाएगी। दादरी से गुजरने वाले एनएच 34 पर भी नई टोल दरें प्रभावी होंगी। टोल प्रबंधन ने इसकी सूचना जारी कर दी है।

यह होंगी नई दरें

नई दरों के अनुसार एकल यात्रा पर कार, जीप, वैन व हल्के वाहनों के लिए 135 के बजाए 140 रुपये टोल शुरू देना होगा। वहीं हल्के वाणिज्यक वाहनों के लिए यह दर 220 रुपये है। अभी तक 210 रुपये वसूले जा रहे थे। बस व ट्रक के लिए नई दरें 450 रुपये होंगी, वर्तमान दर 430 रुपये थी। तीन धुरी वाले वाणिज्यक वाहनों से 660 रुपये के बजाए अब 690 रुपये वसूल किए जाएंगे। भारी वाहन, निर्माण मशीनरी, छह धुरी वाले वाहनों को 840 के बजाए 885 रुपये टोल शुल्क देना होगा।

ट्रक ने आगे जा रही गाड़ी को मारी टक्कर, दुर्घटना के बाद लगी आग, झुलसने से चालक की मौत

ईस्टर्न पेरीफेरल पर बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रक ने आगे जा रहे वाहन में टक्कर मारी। घटना के बाद टक्कर मारने वाले वाहन की केबिन में आग लग गई। आग लगने से चालक की जलकर मौत हो गई।

ग्रेटर नोएडा। ईस्टर्न पेरीफेरल पर बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रक ने आगे जा रहे वाहन में टक्कर मारी। घटना के बाद टक्कर मारने वाले वाहन की केबिन में आग लग गई। आग लगने से चालक की जलकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग के वाहन ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने बताया एक ट्रक सोनीपत से फरीदाबाद ईस्टर्न पेरीफेरल के रास्ते जा रहा था। ट्रक में सोफे का कवर भरा था। ट्रक को बुलंदशहर के डिबाई ऊंचा गांव निवासी चालक धर्मेंद्र चला रहा था। संभावना जताई जा रही है कि आगे चल रहे किसी वाहन ने अचानक ब्रेक मार दी, इस कारण पीछे चल रहे धर्मेंद्र का ट्रक उससे टकरा गया।

आग केविन तक ही सीमित रही

घटना के बाद धर्मेंद्र के ट्रक की केबिन में आग लग गई, दूसरा वाहन मौके से भाग गया। आग की लपटों में धर्मेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने बताया आग केविन तक ही सीमित रह गई, पीछे रखे माल को बचा लिया गया। सीएनजी लगी होने के कारण दुर्घटना के बाद आग लगने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को मौके से हटाकर पेरिफेरल पर वाहनों का आवागमन सही कराया।

इनसाइड

वर्षा के दौरान निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 2 घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती

तेज वर्षा के दौरान बृहस्पतिवार को सेक्टर-44 स्थित निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से दो कामगार घायल गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। घायलों की पहचान 18 साल के अजय व 16 साल एक किशोर के रूप में हुई है।

नोएडा। तेज वर्षा के दौरान बृहस्पतिवार को सेक्टर-44 स्थित निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से दो कामगार घायल गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। एसीपी नोएडा रजनीश वर्मा का कहना है कि घायलों की पहचान 18 साल के अजय व 16 साल एक किशोर के रूप में हुई है।

ऊपरी मंजिल पर चल रहा निर्माण कार्य

दोनों मध्यप्रदेश के रहने हैं। दोनों घायल दिहाड़ी कामगार है। वहीं, सेक्टर-39 कोतवाली प्रभारी अजय चाहर का कहना है कि सेक्टर-44 में मकान में ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे निर्माणाधीन दीवार गिरने से वहां काम कर रहे दो दिहाड़ी कामगार घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए सेक्टर-27 स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर हैं।

141 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर चलाया गया इलेक्ट्रिक इंजन, सफल ट्रायल के बाद अब रवाना होगी मालगाड़ी

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी सेक्शन पर बृहस्पतिवार को बिजली का इंजन दौड़ाने का सफल ट्रायल हुआ। दोपहर करीब एक बजे न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी तक 141 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर बिजली इंजन रवाना किया गया।

नोएडा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी सेक्शन पर बृहस्पतिवार को बिजली का इंजन दौड़ाने का सफल ट्रायल हुआ। दोपहर करीब एक बजे न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी तक 141 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर बिजली इंजन रवाना किया गया।

इस दौरान कई तकनीकी पहलुओं की जांच की गई। रात करीब आठ बजे इंजन न्यू रेवाड़ी पहुंचा। शुक्रवार को न्यू दादरी से न्यू रेवाड़ी तक 750 मीटर लंबी मालगाड़ी को रवाना किया जाएगा। यह मालगाड़ी न्यू रेवाड़ी से भारतीय रेल की लाइन के जरिये मुंबई को रवाना होगी।

परियोजना महाप्रबंधक वाइपी शर्मा ने बताया कि न्यू दादरी से न्यू पृथला के बीच पहले से ही मालगाड़ी का संचालन हो रहा है। इस सेक्शन की लंबाई करीब 54 किलोमीटर है। पिछले दिनों न्यू रेवाड़ी तक का सेक्शन पूरा हो गया था। गुरुग्राम के पास सोहना में 6.25 किमी डीप कट और एक किमी लंबी टनल (सुरंग) का काम अब पूरा हो गया है, जिसके बाद न्यू रोवाड़ी तक मालगाड़ी ले जाने को हरी झंडी मिल गई। वर्तमान में प्रयागराज से न्यू दादरी होते हुए न्यू पृथला तक मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं।

ईस्टर्न कारिडोर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से पंजाब के लुधियाना (1839 किमी) व वेस्टर्न कारिडोर मुंबई से गौतमबुद्ध नगर के दादरी (1504 किमी) के बीच है। मालगाड़ियों के लिए समर्पित इन दोनों कारिडोर पर 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़ेंगी। न्यू दादरी से हरियाणा के न्यू रेवाड़ी सेक्शन पर पांच स्टेशन न्यू रेवाड़ी, न्यू धारूहेड़ा, न्यू मेवात, न्यू पृथला, न्यू फरीदाबाद व न्यू दादरी हैं। इन सेक्शन को चार हजार करोड़ रुपये में एलएंडटी कंपनी व जापान की कंपनी सोजित्ज ने बनाया है।

गुजरात पुलिस की मोदीनगर में दबिश, बिसोखर के मकान में चल रहा था कॉल सेंटर

बिसोखर में अपनी बहन रिहाना के घर पर काल सेंटर चला रहा था। यहां 2300 कनेक्शन थे जिससे रोजाना 26 हजार से अधिक काल होती थी। आरोपितों की भूमिका खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना है।

मोदीनगर। गुजरात पुलिस ने बृहस्पतिवार को मोदीनगर के गांव बिसोखर में काल सेंटर पर छापेमारी कर संदिग्ध भाई-बहन जुनैद और रिहाना को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि काल सेंटर के माध्यम से राष्ट्रविरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थी।

बीस दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में हुए भारत-आस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच से पहले अहमदाबाद में कई लोगों को आरोपितों ने काल कर धमकी दी थी। लोगों में डर फैलाने का आरोपितों का उद्देश्य था। मौके से गुजरात पुलिस ने सिम बाक्स, एमप्लिफायर, छह मोबाइल, पेन ड्राइव समेत अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले 15 दिन से गुजरात पुलिस गाजियाबाद व मेरठ में दबिश दे रही थी।

खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने की चर्चा

पहले पुलिस मेरठ पहुंचीं लेकिन वहां उन्हें पता चला कि आरोपित जुनैद तो मेरठ के मवाना से भागकर मोदीनगर के बिसोखर आ गया है। पुलिस के मुताबिक, काल करने का उद्देश्य लोगों में डर बैठाना था। इनके खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने की चर्चा है। आरोपितों का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला है।

आगे की कार्रवाई शुरू

दो महीने से मोदीनगर के बिसोखर में यह काल सेंटर चल रहा था। एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि गुजरात की क्राइम ब्रांच टीम ने मोदीनगर थाने में आमद कराई थी। यहां से दोनों आरोपितों को पकड़कर वे गुजरात ले गई है। वहीं से आगे की कार्रवाई होगी।

CA और उनकी पत्नी पर लूट के लिए किया चाकू और हथौड़े से वार, आरोपित दंपती गिरफ्तार

इंदिरपुरम थाना क्षेत्र में घर में घुसकर सीए और उनकी पत्नी पर लूट का विरोध करने पर हमला करने वाली आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद। साहिबाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली थाना क्षेत्र के अभय खंड पुलिस चौकी के पास घर में घुसकर सीए और उनकी पत्नी पर लूट का विरोध करने पर हमला करने वाली आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घायल सीए रविकांत शर्मा और उनकी पत्नी गीता की हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को दोनों की वैशाली के निजी अस्पताल में सर्जरी हुई है। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन विवेक चंद यादव ने बताया कि आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों से पूछताछ की जा रही है। एक के एचआईजी मकान में रहने वाले 62 वर्षीय सीए रवी कांत शर्मा और उनकी पत्नी 58 वर्षीय गीता शर्मा को बृहस्पतिवार दोपहर करीब 1:30 बजे मिस्त्री और उसकी पत्नी ने घर में घुसकर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया था। पकड़े जाने के डर से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर आरोपित भाग गए थे। भागते हुए आरोपित दंपती सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। चार टीमें आरोपित की तलाश में जुटी थी।

1 अप्रैल से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क पंजीकरण की ज्वेलरी, अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य

आज से यानी एक अप्रैल से देश में प्रत्येक छोटे और बड़े ज्वेलर के लिए हॉलमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। बिना पंजीकरण के दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हॉलमार्क का पंजीकरण नहीं होने पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) कार्रवाई करेगा।

गाजियाबाद। एक अप्रैल से देश में प्रत्येक छोटे और बड़े ज्वेलर के लिए हॉलमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। बिना पंजीकरण के दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हॉलमार्क का पंजीकरण नहीं होने पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) कार्रवाई करेगा।

गाजियाबाद बीआइएस ब्रांच के निदेशक एसके दत्ता ने कहा कि इन जिलों गाजियाबाद में 535, मुरादाबाद 259, रामपुर 29, संभल 14, मेरठ 618, हापुड़ 47, बागपत 42, अमरोहा 40 और पूर्वी दिल्ली 400 ज्वेलरों ने हॉलमार्क का पंजीकरण कराया हुआ है। जबकि इन जिलों में ज्वेलरों की संख्या इससे कही अधिक है। अभी 50 फीसदी से ज्यादा ज्वेलरों के भी पंजीकरण नहीं कराया है।

संभल में महज 14 ज्वेलरों ने पंजीकरण कराया हुआ है। इसी तरह हापुड़, अमरोह, बागपत व रामपुर में तो 10 फीसदी ज्वेलरों ने हॉलमार्क पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे में बीआइएस की टीम को यहां पर ज्यादा कार्रवाई करनी होगी। एक अप्रैल से हॉलमार्क लाइसेंस लेना अनिवार्य होने पर ग्राहकों को भी इसका ध्यान रखना होगा। बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी खरीदने पर ग्राहकों को नुकसान होता है। ज्वेलर को दुकान के बाहर या अंदर लिखवाना होगा कि उनके पास हॉलमार्क पंजीकरण है। ज्वेलर घर बैठे निश्शुल्क बीआइएस की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।

ऐसे करें पहचान

रत्येक ज्वेलरी पर एचयूआइडी (हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटीफिकेशन) नंबर होता है। यदि कान की दो बाली खरीद रहे हैं तो दोनों बाली पर अलग-अलग नंबर होता है। आपको अपने मोबाइल में बीआइएस केयर एप इंस्टाल करना होगा। एप पर ज्वेलरी पर लिखी एचयूआइडी नंबर डालना होगा। उसका पूरा विवरण खुलकर सामने आ जाएगा। पंजीकरण नंबर से लेकर कहां पर इसको हॉलमार्क कराया गया है, यह सब जानकारी होगी।

हॉलमार्क आइडी नहीं होने पर आप एप पर ही इसकी शिकायत बीआइएस के अधिकारियों से कर सकते हैं। बीआइएस की टीम उस ज्वेलर पर कार्रवाई करेगी। देश में अभी करीब 1338 हॉलमार्किंग केंद्र हैं। जिन पर जांच परखने के बाद सोने पर हॉलमार्क किया जाता है।

गांवों में भी जाएगी बीआइएस की टीम

गांवों में बड़ी संख्या में ज्वेलरों की दुकाने हैं। अभी तक बीआइएस की टीम ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही कार्रवाई करने जाती थी लेकिन अब गांवों में भी कार्रवाई करने जाएगी। इसके लिए बीआइएस ग्रामीण ग्राहकों को हॉलमार्क के प्रति जागरूक भी करेगी। जिससे ग्राहक ज्वेलर के पास हॉलमार्क लाइसेंस नहीं होने पर बीआइएस केयर एप पर शिकायत कर सकें।

इनसाइड

Maruti Suzuki Fronx और Mahindra XUV 300 की ये हैं खूबियां, दोनो में कौन कितनी बेहतर

Maruti Suzuki Fronx और Mahindra XUV 300 के सभी फीचर्स डायमेंशन और इंजन विकल्प के बारे में जान लीजिए। दोनो SUV डुअल टोन इंटीरियर के साथ आती हैं। इसके अतिरिक्त XUV 300 में रियर डिस्क ब्रेक्स हैं जो Fronx में नहीं दिखेंगे।

नई दिल्ली। जापानी कार निर्माता कंपनी Maruti ने हाल ही में अपनी Fronx SUV को अनवील किया था। कंपनी जल्द ही इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। मारुती की ये एसयूवी Balena हैचबैक पर आधारित है और इसे दो इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया है। इनमें एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.0-लीटर बूस्टर जेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है। अनुमान है कि Maruti Suzuki Fronx की शुरुआती एक्स शोरूम कीमतें 7.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती हैं। लॉन्च होने के बाद ये कार Hyundai Venue, Mahindra XUV 300, Kia Sonet, Nissan Magnite और Renault Kiger जैसी अन्य कॉम्पैक्ट SUV की टोली में शामिल हो जाएगी। अपने इस लेख में हम आपको Mahindra XUV300 और Maruti Suzuki Fronx के फीचर्स, डायमेंशन और इंजन विकल्प के बारे में बताने जा रहे हैं।

डिजाइन

Fronx की बात करें तो इसमें एलईडी हेडलैंप के साथ एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। वहीं XUV 300 में हैलोजन हेडलैंप सेटअप के साथ एलईडी डीआरएल मिलते हैं। दोनों कारों में रियर वाइपर और वॉशर के साथ एक एलईडी टेल लैंप सेटअप दिया गया है। एक्सयूवी 300 में 17 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील मिलते हैं जबकि फ्रोंक्स में 16 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त XUV 300 में रियर डिस्क ब्रेक्स हैं जो Fronx में नहीं दिखेंगे।

इंटीरियर

दोनो SUV डुअल टोन इंटीरियर के साथ आती हैं। फीचर्स की बात करें तो Fronx में कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी के साथ 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay, Android Auto, Arkamys-tuned साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हाइट अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक एसी, रियर एसी वेंट, एचयूडी डिस्प्ले और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं इसमें 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड असिस्ट के साथ ईएसपी जैसे सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं।

भारतीय बाजार में आ गई 3.69 करोड़ रुपये वाली कार, जानें इसमें क्या कुछ खास

Maserati MC20 supercar लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय बाजार में 3.69 करोड़ रुपये में Maserati MC20 supercar कार लॉन्च हो गई है। MC20 का इंजन मिड-माउंटेड है। चलिए आपको इस कार से जुड़ी खास बात बताते हैं।

नई दिल्ली। Maserati ने सबसे पहले MC20 सुपर कार को 2020 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था। लेकिन, अब वाहन निर्माता कंपनी ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने का फैसला किया है। आपको बता दें, इस सुपकार की कीमत 3.69 करोड़ एक्स-शोरूम है। ये कीमत किसी भी ग्राहक के कार सेलेक्ट करने से पहले की है। वहीं MC12 के विपरीत, जो Ferrari Enzo पर आधारित था, MC20 एक बिल्कुल नया मॉडल है। कंपनी Maserati MC 20 के लिए 3.0-लीटर V6 इंजन का इस्तेमाल कर रही है। यह 630 बीएचपी और 730 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

Maserati MC20

MC20 का इंजन मिड-माउंटेड है, जिसमें 3.0-लीटर V6 इंजन है। लेकिन मासेराती का कहना है कि वे F1 की पेटेंट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इंजन 630 hp और 730 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है जो पावर को केवल रियर व्हील्स तक ट्रांसफर करता है। इस कार में ड्राइवर चार अलग-अलग ड्राइविंग मोड भी सलेक्ट कर सकते हैं।

यह कार 2.9 सेकंड के अंदर 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 325 किमी प्रति घंटे से अधिक है। वहीं MC20 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 33 मीटर से भी कम दूरी पर रुक सकती है।

Maserati MC20 वजन

आपको बता दें, इस कार के वजन को कम करने के लिए काफी कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। जिसके कारण इस कार का वजन 1.5 टन से कम है और इसका वजन 59 प्रतिशत पीछे और 41 प्रतिशत सामने है। MC20 की चेसिस मोनोकॉक टाइप की है और इसका वजन सिर्फ 100 किलोग्राम है। वहीं इस कार का एक्सटीरियर काफी क्लीन और मिनिमलिस्टिक है। इसका कुछ स्टाइल MC12 से लिए गए हैं।

भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Huracan और Ferrari 296 GTB से है।

Airbag क्या है, कैसे करता ये काम और सभी कारों में इसका होना क्यों है जरूरी?

Airbag ये एक सुरक्षा उपकरण है। साल 2019 में सरकार ने देश की सभी कार में इसे स्टैंडर्ड रूप से पेश करने का आदेश दिया था। अगर आपकी कार में फ्रंट एयरबैग भी दिए गए हैं तो दुर्घटना की स्थिति में ये आपके बहुत काम आएंगे।

नईदिल्ली। जब हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो अमूमन हमारा सवाल रहता है कि इसमें कितने एयरबैग हैं? क्या आपको पता है कि एयरबैग का कार में होना क्यों जरूरी है और सरकार इसे सभी कारों में अनिवार्य रूप से देने के लिए क्यों बोलती है। अगर आपका जवाब नहीं है तो हम आपको अपने इस लेख में एयरबैग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले एयरबैग को 1950 के दशक में खोजा गया था। यह सुरक्षा उपकरण सरकार द्वारा भारतीय कारों में 2019 से अनिवार्य कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि एयरबैग क्या होता है और ये कैसे काम करता है।

क्या है Airbag

Airbag एक सुरक्षा उपकरण है। साल 2019 में सरकार ने देश की सभी कार कंपनियों को इसे स्टैंडर्ड रूप से अपने मॉडलों में पेश करने को कहा था। सरकार का आदेश था कि वाहन निर्माता कंपनी अपनी कार के सभी मॉडल्स में कम से कम दो एयरबैग देंगी। जैसा कि इसका नाम है Airbag है, ये एक कॉटन का बना हुआ थैला होता है जो दुर्घटना की स्थिति में पैसेंजर को बचाने के काम आता है। कंपनियां इसे कार के स्टीयरिंग व्हील, दरवाजे और डैशबोर्ड पर लगाती हैं।

कैसे करता है काम

एयरबैग किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों के सिर, गर्दन या छाती को कार के अंदर टकराने से बचाने के लिए होता है। एयरबैग सेंसर द्वारा सक्रिय होता है जो 20-40 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की गति पर कार में किसी वाहरी वस्तु के प्रभाव का पता लगा लेता है। बजट कारों में आमतौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग ही मिलते हैं। ये एयरबैग स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड दोनों से खुलते हैं। आगे वाले एयरबैग के सेंसर आमतौर पर फ्रंट बम्पर के बीच स्थित होते हैं जबकि साइड एयरबैग के लिए दरवाजे पर सेंसर लगाए जाते हैं। देश में सभी कारों में 2 फ्रंट एयरबैग होना अनिवार्य है। वहीं कंपनियां अपने मंहगे मॉडल में 10 से भी अधिक एयरबैग ऑफर करती हैं।

Airbag क्यों हैं जरूरी

अगर आपकी कार में फ्रंट एयरबैग भी दिए गए हैं तो दुर्घटना की स्थिति में ये आपके बहुत काम आएंगे। जैसे ही कार में लगे सेंसर को आभास होता है कि सामने से 20-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कोई दवाब पड़ा है तो वह एयरबैग को खोल देता है। ऐसे में यात्री घायल होने से काफी हद तक बच जाते हैं। बशर्ते कार की टक्कर ज्यादा भीषण न हुई हो।

नई सोनाटा को पहली बार में किया गया पेश, मिली ये जानकारी

2023 Hyundai Sonata उत्तर कोरिया में हो रहे 2023 Seoul Motor Show में Hyundai ने अपनी इस नई सेडान कार को दिखाया है। इसके बारे में कंपनी ने क्या जानकारी साझा की है और कितनी खास है 2023 Hyundai Sonata आइए आपको इस लेख में बताते हैं।

नई दिल्ली। कोरियन कार निर्माता कंपनी ह्यूंडई ने हाल ही में 2023 Hyundai Sonata को वैश्विक रूप से अनवील किया था। कंपनी ने अब अपनी इस सेडान कार को जनता के सामने पेश कर दिया है। दरअसल कंपनी ने 2023 सियोल मोटर शो में 2023 Hyundai Sonata को पहली बार लोगों के सामने पेश किया। इसे देखने के लिए काफी मात्रा में भीड़ उमड़ गई। कंपनी अपनी इस अपडेटेड Sonata को सबसे पहले कोरियाई बाजार में बेच सकती है। इसके बारे में कंपनी ने क्या जानकारी साझा की है और कितनी खास है 2023 Hyundai Sonata आइए आपको इस लेख में बताते हैं।

2023 Hyundai Sonata को लेकर ये जानकारी आई सामने उत्तर कोरिया में हो रहे 2023 Seoul Motor Show में Hyundai ने अपनी इस नई सेडान कार को दिखाया है। साथ ही कंपनी ने इसके बारे में कुछ जानकारी भी साझा की हैं। कंपनी ने बताया है कि 2023 Hyundai Sonata कुल तीन पावरट्रेन विकल्पों से लैस होगी। हालांकि अभी तक इसके इंजन की शक्तियों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। हुंडई अपनी अपडेटेड सोनाटा को इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही में अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने से पहले दक्षिण कोरिया बाजार में बेच सकती है।

फीचर्स, डिजाइन और इंजन

Hyundai अपनी इस सेडान कार में हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और लेयर्ड डैशबोर्ड जैसे फीचर्स ऑफर कर सकती है।

सामने से देखा जा सकता है कि 2023 Hyundai Sonata में अधिक मस्कुलर बोनट, एक संशोधित हेडलैम्प क्लस्टर और एक नया ग्रिल सेक्शन दिया गया है। साथ ही इसमें एक एलईडी लाइट बार, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और नया साइड गार्निश दिया गया है।

इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड

Kia EV9 के बारे में जानें खास बातें

Kia EV9 Kia EV9 इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (E-GMP) पर बेस्ड है।ये एक दमदार लाइटिंग तकनीक के साथ आती है। Kia EV9 एक बार चार्ज करने पर 541 किमी की रेंज देती है। इसका केबिन कई दमदार फीचर्स से लैस है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद किआ ने अपनी Kia EV9 एसयूवी का अनावरण कर दिया है। जिसे इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था। कंपनी ने प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल में थोड़े बदलाव किए है। तीन रो वाली एसयूवी कई दमदार फीचर्स के साथ आती है। कंपनी ईवी9 को अपना नया फ्लैगशिप मान रही है। चलिए आपको इस कार की खास बात बताते हैं।

Kia EV9 : लाइटिंग

किआ ईवी9 एक दमदार लाइटिंग तकनीक के साथ आती है, जिसे डिजिटल टाइगर फेस कहा जाता है। कार को फ्रंट ग्रिल पर नई लाइटिंग स्कीम मिलती है। इसमें ट्विन वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स के पास छोटे क्यूब लैंप्स के डुअल क्लस्टर हैं जो एक एनिमेटेड लाइटिंग पैटर्न बनाते हैं। कंपनी का दावा है कि EV9 के मालिक डिजिटल टाइगर फेस के डिजाइन को बदल भी सकते हैं।

Kia EV9 : प्लेटफार्म

आपको बता दें, Kia EV9 को वाहन निर्माता कंपनी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (E-GMP) पर बेस्ड है। जिसे Hyundai Ioniq 5 के साथ साझा किया गया है। EV9 में 122 इंच का व्हीलबेस है और इसकी लंबाई 197 इंच है।

Kia EV9 : केबिन फीचर्स

Kia EV9 के केबिन में आपको कई दमदार फीचर्स मिलते हैं। इसमें डिजिटल स्क्रीन है जो ड्राइवर की सीट से केंद्र बिंदु तक फैली हुई है। इसके अलावा, ईवी जो सात और छह-सीटर ऑप्शन में आती है। इसमें कैमरा 180 डिग्री घूम सकता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ईवी चार्ज हो रही है।

Kia EV9 : ADAS

भारतीय बाजार में किआ ईवी9 जीटी-लाइन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) के साथ आती है। इसमें हाईवे ड्राइविंग पायलट मिलता है जिसके कारण हैंड्स-फ्री ड्राइव करने का अनुमति देता है। एडीएएस 15 सेंसर के आधार पर काम करता है, जिसमें पूर्ण 360 डिग्री कैमरे का इस्तेमाल होता है।

Kia EV9 : पावरट्रेन

Kia EV9 की एक बार चार्ज करने पर 541 किमी की रेंज देती है। इसमें 150 kW इलेक्ट्रिक मोटर है जो EV को 9.4 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसमें 160 kW इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है जिसके कारण कार 8.2 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। किआ का दावा है कि ईवी9 महज 15 मिनट की चार्जिंग में 239 किमी चल सकती है।

शिक्षा-खेल विभाग में समन्वय स्थापित हो

भूपिंदर सिंह

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कदम-कदम पर विद्यालय खुलने तथा विद्यालय से घर तक आना-जाना जब अब वाहन से हो रहा है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण परिवेश भी अब शहरों व कस्बों में बदल रहा है

आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडऩा तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक क्रियाओं को करने से रक्त संचार तेज हो जाता है'

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कदम-कदम पर विद्यालय खुलने तथा विद्यालय से घर तक आना-जाना जब अब वाहन से हो रहा है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण परिवेश भी अब शहरों व कस्बों में बदल रहा है, ऐसे में विद्यार्थियों के आराम की सुख-सुविधाओं में तो बढ़ौतरी हो रही है, मगर उन का फिटनेस स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। इसलिए विद्यालय स्तर से फिटनेस कार्यक्रम की बहुत ज्यादा जरूरत है व इसके लिए शिक्षा और खेल विभाग में समन्वय स्थापित करना जरूरी हो जाता है ताकि हम विद्यालय स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम लागू कर सकें। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, विद्यालय प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर सचेत हो जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते आते समझदार हो गया होता है।

माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विद्याओं में व्यस्त रखने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडऩा बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है।

पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य था। इस सबके पीछे कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों की दूरगामी सोच थी। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है।

यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार चालीस प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए। हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना है। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गये हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करता था। विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है।

पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडऩा तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडने व शारीरिक क्रियाओं को करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें विद्यालय व घर पर उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम देना होगा। तभी हम सही अर्थों में अपनी अगली पीढ़ी को संपूर्ण शिक्षित करने का दम भर सकते हैं। आशा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की नयी कांग्रेस सरकार इस विषय पर जरूर और जल्द ध्यान देगी।

संपादक की कलम से

कर्नाटक का 'कोटावादी' चुनाव

कर्नाटक में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा और 13 मई को जनादेश सार्वजनिक कर दिया जाएगा। पहली अग्निपरीक्षा भाजपा की है, क्योंकि वह सत्तारूढ़ है। दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार और चुनावी स्वीकृति के लिए यह चुनाव जीतना अनिवार्य है। सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, जो यह चुनाव जीत कर अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहेगी और भाजपा का एक दुर्ग ढहा कर 2024 के लिए अपनी दावेदारी और मानसिक तैयारी मजबूत करना चाहेगी। कर्नाटक 2023 का बड़ा राज्य है, जहां 224 विधानसभा सीटों के लिए जनादेश प्राप्त करना है और 28 लोकसभा सीटों की ज़मीन तैयार करनी है। भाजपा और कांग्रेस की पहली कोशिश स्पष्ट जनादेश लेने की होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जद-एस भी चुनावी मैदान में है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा करीब 90 साल के हो चुके हैं, लिहाजा इसे अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। लोगों की संवेदनाएं उनसे भी जुड़ी हैं। वैसे 1985 के बाद से कर्नाटक में सत्ता पक्ष की वापसी नहीं हुई है। हिमाचल में नाकामी के बाद भाजपा कर्नाटक में भी 'रिवाज़ बदलने' पर आमादा है। चूंकि मौजूदा बोम्मई सरकार के खिलाफ कोई लहर-सी स्थिति नहीं है, लिहाजा भाजपा की रणनीति में जातीय आरक्षण ऐसा मुद्दा है, जिसके जरिए धुरवीकरण के हालात पैदा किए जा सकते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार ने दलितों का आरक्षण 15 फीसदी से बढ़ा कर 17 फीसदी और अनुसूचित जनजाति का कोटा 5 फीसदी से 7 फीसदी किया है। बीते शुक्रवार मुसलमानों का कोटा 4 फीसदी कम कर दिया गया। यह कोटा कर्नाटक के ताकतवर और आर्थिक रूप से समृद्ध जातीय समूहों-लिंगायत और वोक्कालिंगा-में बांट दिया गया है। इन समूहों का ओबीसी आरक्षण के तहत पहले से ही कोटा तय है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा लिंगायतों के कद्दावर, स्वीकृत नेता हैं। यकीनन सरकार के इन फैसलों से कर्नाटक का जातीय संतुलन जरूर गड़बड़ाएगा, लिहाजा असंतोष और विरोध-प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पथराव तक किया जा चुका है। हालांकि मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस वर्ग में आर्थिक आरक्षण के तहत कोटा मिलता रहेगा। कर्नाटक में लिंगायत 17 फीसदी हैं और वोक्कालिंगा 15 फीसदी हैं। ओबीसी करीब 35 फीसदी हैं। भाजपा की रणनीति इन जातीय समूहों के अधिकतम वोट हासिल करने की है। उनके जरिए वह कमोबेश 125 सीटें जीतने के गणित पर काम कर रही है। हालांकि उसका चुनावी लक्ष्य 150 से अधिक सीटें जीतने का है। भ्रष्टाचार, विकास, धर्मांतरण, धुरवीकरण, महंगाई, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, बेरोजग़ारी आदि भी प्रासंगिक चुनावी मुद्दे रहेंगे, लेकिन जातीय आरक्षण सबसे संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि यह आम आदमी के हितों और बहुआयामी भविष्य से जुड़ा है। भाजपा ने 2019 में कांग्रेस-जद (एस) की साझा सरकार में तोडफ़ोड़ कर, विधायकों के पालाबदल करा अपनी सरकार बनाई थी, तो उसने सांप्रदायिकता के साथ-साथ जातीय आरक्षण के मुद्दे को भी उबाले रखा।

हिजाब, धर्मांतरण और टीपू सुल्तान की विरासत के जरिए धुरवीकरण को भी जिंदा रखा। इस तरह भाजपा हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती थी और विभिन्न जातीय समूहों के वोट को बांट देना चाहती थी। उसमें कमोबेश वह सफल रही। 1970 के दशक में कांग्रेस नेता देवराज अर्स ने ओबीसी, दलित, जनजाति और अल्पसंख्यकों को लामबंद करने में कामयाबी हासिल की थी, नतीजतन लिंगायत और वोक्कालिंगा के राजनीतिक वर्चस्व को बेअसर किया था। अर्स का फॉर्मूला 1980 के दशक में, जनता पार्टी के उभार के बाद, पिट गया। उसके बाद लिंगायत बुनियादी तौर पर भाजपा को और वोक्कालिंगा जद-एस को समर्थन देते रहे हैं।

भाव

हिंदी कविता का फेसबुकवादी युग

जहां तक मैंने हिंदी कविता की नकली से नकली गाइड में पढ़ा है, हिंदी कविता में सबसे पहले वीरकाव्य आया। फिर भक्तिकाव्य। उसके बाद रीतिकाव्य आया तो उसके बाद आधुनिक कविता। हिंदी कविता अ कविता, न कविता, फ कविता, ट कविता, ह कविता से गुजरती हुई आज फेसबुकवादी कविता की काया में प्रवेश कर गई है। हिंदी कविता में फेसबुकवादी कविता का आरंभ वैसे तो फेसबुक के उदय के साथ ही हो गया था। फेसबुक का उदय होते ही कुछ संपादकों के अभिवादन और खेद सहित लौटती कविताओं के कवियों ने इस सबसे मुक्ति पाने के लिए फेसबुक पर कविता चेपने का प्रयोग किया। जब उन्हें लगा कि उनका यह प्रयोग सफल रहा तो उनकी देखा देखी में फेसबुक पर अपनी कविताओं के प्रकाशन के लिए संपादकों के सताए कुछ और कविता के इस नए आंदोलन में उनके साथ शरीक हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का सबसे खूंख्वार हिंदी आलोचक मैं प्राचार्य वामचंद्र कुक्ल इसे हिंदी कविता में फेसबुकवाद का बीजवपन काल कहता हूं। परंतु हिंदी कविता में फेसबुकवादी कविता का तूफानी आरंभ केवल मेरे जैसा कब्ज प्रतिष्ठित, मूर्धन्य समीक्षक कोरोना काल से मानता है। कोरोना काल में फेसबुकवादी कविता और कवियों की फेसबुक पर बाढ़ आ गई।

न कोरोना आता, न फेसबुकवादी कविता आज अपने उच्चतम स्तर पर होती। हालांकि इसी बीच बड़े शोर शराबे के साथ आधुनिक हिंदी कविता में कविता का व्हाट्सएप युग भी आया हालावाद की तरह। पर बहुत जल्दी ही वह गुडमार्निंग, गुडनाइट में सिमट कर रह गया। आधुनिक हिंदी कविता के आंदोलन में जब फेसबुकवादी कविता का आरंभ हुआ तब इन फेसबुकिया कविताओं के कवि अपनी कविताओं के कवि भी खुद थे और पाठक भी खुद ही थे। क्या हुआ जो किसी ने गलती से उनकी फेसबुकिया कविता को कभी कभार एक आध अंगूठा दिखा दिया। आधुनिक हिंदी कविता आंदोलन में फेसबुकवादी कविता के विकास के पीछे पत्र, पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा कविता छपने के बाद कवि को पारिश्रमिक न देना भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। तब कविता की फेसबुक धारा के कवियों ने सोचा कि क्यों न संपादकों का मुफ्त में छापने का अहसान लेने के बदले फेसबुक पर ही कविता चेपी जाए। पारिश्रमिक तो न वहां है, न यहां। यहां पर लिखने से कम से कम कविता को संपादक के फोके अभिवादन और खेद सहित लौटाने की पीड़ा से मुक्ति तो मिलेगी। इसके चलते भी आधुनिक हिंदी कविता में फेसबुकवादी कविता ने देखते ही देखते उग्र आंदोलन का रूप धारण कर लिया। हिंदी कविता में फेसबुकवादी कविता को सेमी मान्यता मिलने के बाद आज प्रतिष्ठित से लेकर लब्ध प्रतिष्ठित कवि तक फेसबुक पर अपनी कविता चेपने को अपना सौभाग्य समझने लगे हैं। कोरोनाकाल को आधुनिक हिंदी कविता के फेसबुकवादी युग का यौवन काल कहा जा सकता है। कोरोनाकाल के आरंभ में जब अखबार छपने बंद हुए, पत्रिकाएं निकलनी बंद हुईं तो प्रतिष्ठित कवि तक काव्यात्मक अपच निकालने को बेचैन हो उठा। कोरोनाकाल में हिंदी कविता को बचाने का श्रेय फेसबुकिया कवियों को ही जाता है। हालांकि अब कोरोना का कहर कम हो गया है। अखबार, पत्रिकाएं फिर से गिरते पड़ते निकलने लगे हैं। कुछ पत्र, पत्रिकाएं कोरोनाकाल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी स्वर्ग सिधार गए। जो बचे, उनमें साहित्य के अन्य कॉलमों की तरह कविता का भी कॉलम मर गया।

आगामी चुनाव और विपक्ष की रणनीति

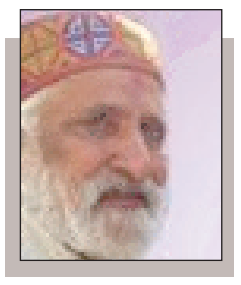

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

लोकसभा का आगामी चुनाव अत्यन्त महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देश में भी और विदेश में भी। उसका कारण है। आज तक देश में तीन प्रकार की सरकारें रही हैं। कांग्रेस द्वारा अपनी कार्यकारिणी में भारत के विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त, ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमीनियन का दर्जा देना स्वीकार कर लिया था और उस डोमिनियन की कमान पंडित जवाहर लाल नेहरू को सौंप दी थी। लेकिन यह ध्यान रखा कि डोमीनियन का गवर्नर जनरल अभी भी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि लार्ड माऊंटबेटन ही रहे। इसका ब्रिटिश सरकार को लाभ यह हुआ कि माऊंटबेटन ने जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में करवा दिया, मामला सुरक्षा परिषद में लटका दिया जिसके कारण देश के संविधान में अनुच्छेद 370 ने जन्म ले लिया। यह कांग्रेस की पहली सरकार थी, जिसने देश के लिए भावी रणनीति तय कर दी थी। कांग्रेस की यह सरकार मोटे तौर पर 1947 से लेकर 1997 तक चली। बीच में तीन-चार साल गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं, लेकिन वे सरकारें तकनीकी तौर पर ही गैर कांग्रेसी कही जा सकती हैं क्योंकि वे सरकारें भी मोटे तौर पर व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस से रूठे हुए कांग्रेसियों की ही सरकारें थीं। इसलिए देश के शासन में किन्हीं नीतिगत परिवर्तनों की आशा नहीं की जा सकती थी। सरकार की देश को लेकर सोच और दिशा वही रही जो पंडित जवाहर लाल नेहरू और लार्ड माऊंटबेटन तय कर गए थे।

यही कारण था कि पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमले करता रहा, भारतीय सेना शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सरकारें मेज पर सेना की जीत को हार में बदलती रहीं। चीन ने भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और भारत सरकार फिर भी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर दिलवाने के लिए दिन-रात एक करती रही। 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सरकार रही। परन्तु वह चौबीस परस्पर विरोधी दलों की सरकार थी। अगले दस साल तक पुनः कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाले रखी। लेकिन यह भी तकनीकी तौर पर ही कांग्रेस की सरकार कही जा सकती थी। वास्तव में यह सोनिया माईनो गान्धी, जिसने खाँटी कांग्रेसी सीता राम केसरी को बैठक में से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, की सरकार ही थी जो वह अपने दरबारियों जिन्हें नैशनल कौंसिल का नाम दे रखा था, के माध्यम से चला रही थीं। लेकिन भारतीय संविधान में सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसलिए उस पद पर मनमोहन सिंह जी को बिठा रखा था। इसलिए यदि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के छह साल निकाल दिए जाएं तो 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के लोगों की सरकार ही रही। ये सरकारें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को बहुत ही मुफीदकारी लगती थीं। सोनिया माईनो गान्धी की सरकार तो वैटिकन के राष्ट्रपति को एक प्रकार से अपनी ही सरकार लगती थी। यही कारण था कि उन दिनों चर्च हर रोज़ दिवाली मनाता था। इन सरकारें ने मानसिक रूप से ही तय कर रखा था कि देश को विश्व राजनीति के पिछवाड़े में ही रखना है। आर्थिक नीतियां इस प्रकार की रखी जाएं कि औद्योगीकरण में देश रेंगता रहे। जहां तक देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न था, इन सरकारों का निश्चित मत था कि देश की संस्कृति ही देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह देश का मानसिक पिछड़ापन है। इसलिए ये सरकारें भारत के विसंस्कृतिकरण को नीति का हिस्सा बनाती थीं। कुल मिला कर देश को विश्व शक्तियों का पिछलग्गू बना कर रखना भारत सरकार की आधिकारिक नीति थी। यही कारण था कि यह नीति रूस, चीन और अमेरिका को एक साथ ही अपने अनुकूल लगती थी। लेकिन 2014 में देश के लोगों ने इन नए-पुराने कांग्रेसियों से सत्ता लेकर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी। पिछले तीस साल से बीस-बीस दल मिल कर भारत जैसे महान देश की सरकार चला रहे थे। ऐसी सरकारें देश को कोई निश्चित दिशा नहीं दे पाई। दिशाविहीन भारत उन सभी महाशक्तियों को अनुकूल लगता है जो दुनिया की दिशा अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों के अनुकूल ढालना चाहती हैं।

लेकिन नरेन्द्र मोदी के आने से सारा परिदृश्य ही बदल गया। सबसे पहले तो देश ने सीमाओं को लेकर ढुलमुल नीति से किनारा किया। पूर्वोत्तर भारत में विकास ने गति पकड़ी। सडक़ें, रेल की पटरी बनने लगीं। हवाई अड्डे बनने लगे। सबसे बढ़ कर तिब्बत की सीमा से लगते इलाके में विकास होने लगा। जाहिर है इससे चीन तिलमिलाता। चीन तभी तक भारत का मित्र है जब तक भारत चीन की गतिविधियों की ओर से आंख मूंदे रहता है। जब भारत जागता है तो चीन को लगता है भारत अपनी परम्परा को छोड़ रहा है। चीन के लिहाज़ से भारत की परम्परा भारत द्वारा तिब्बत और लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाक़ों पर चीन को कब्जा कर लेने की अनुमति देना ही है। लेकिन अब भारत डोकलाम और गलवान में चीन से भिड़ रहा है। जाहिर है चीन चाहेगा कि किसी भी तरह मोदी की सरकार हटनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार के वे पुराने दिन लौट आएं। इसी प्रकार पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेजता था। हुर्रियत कान्फ्रेंस के नेताओं को दिल्ली में अपने दूतावास में बुला कर ख़ातिरदारी करता था। मुम्बई में नरसंहार करता करवाता था। भारत में एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) मूल के लोग खुले आम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी की बात करते थे। लेकिन सोनिया गान्धी की सरकार कहा करती थी कि बेचारा पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। लेकिन नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आ जाने से कांग्रेसी सरकारों और पाकिस्तान का वह सुहाना सफर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला करवाया तो भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुस कर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ।

कांग्रेसियों और पाकिस्तान दोनों के चेहरे सूख गए। दोनों ने एक स्वर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार यहीं नहीं रुकी। अनुच्छेद 370 के बहाने कश्मीर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बताने वाले गैंग का मुंह अनुच्छेद 370 को मार कर बंद कर दिया। कांग्रेस और पाकिस्तान ने इतना चिल्लाना शुरू किया कि भारतीयों को यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि अनुच्छेद 370 के हटने पर कौन ज्यादा दुखी है? कांग्रेस या पाकिस्तान? यही कारण है पाकिस्तान भी चाहता है कि किसी भी तरीके से हिन्दुस्तान से मोदी सरकार हटनी चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड को हिन्दुस्तान तब तक ही प्यारा लगता है जब तक वह पूरी वफादारी से ब्रिटिश काल की विरासत ढोता रहे और अपनी सनातन विरासत को छोड़ कर ब्रिटिश सत्ता की विरासत को ही अपनी विरासत घोषित कर दे। अभी तक कांग्रेस सरकारें यही करती आ रही थीं। लेकिन मोदी सरकार आ जाने के बाद मामला बदल गया।

> "यही कारण है कि अमरीका सरकार सार्वजनिक रूप से कह रही है कि हम हिंदुस्तान की सरकार की गतिविधियों पर तीखी नजर रखे हुए हैं। बीबीसी मोदी विरोधी ताकतों को कच्चा माल मुहैया करवा रही है'

चिंतन विचार

क्रेडिट एजेंसियों की प्रासंगिकता

डा. अश्विनी महाजन

अलग-अलग देशों की अपनी रेटिंग एजेंसियां हो सकती हैं। ऐसे में चंद एजेंसियों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। साथ ही इन रेटिंग एजेंसियों के पास खुद निवेशकों से पैसे कमाने की व्यवस्था होना चाहिए'

वर्ष 2007-08 के दौरान अमरीकी अर्थव्यवस्था एक भयंकर त्रासदी से गुजरी और लेहमन ब्रदर्स के साथ-साथ सैकड़ों अमरीकी बैंक दिवालिया हो गए थे। जैसा कि होता रहा है अमरीका के वित्तीय संकट के कारण पूरे यूरोप के बैंकों पर भी भारी संकट आया और इस वित्तीय संकट ने दुनिया भर के देशों पर भी कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत इस संकट से अछूता है क्योंकि भारतीय बैंकों का कोई विशेष एक्सपोजर पश्चिम के इन बैंकों के साथ नहीं है। हालांकि अमरीकी और यूरोपीय देशों पर आए इस संकट की वजह से भारत के निर्यातों पर कुछ न कुछ असर जरूर हुआ, लेकिन भारत की ग्रोथ की यात्रा बदस्तूर जारी रही और भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढने वाले मुल्कों में बना रहा। हालांकि वर्ष 2007-08 का यह संकट अमरीकी सरकार द्वारा 3 खरब डालर (3000 अरब डालर) की सहायता उस समय तो टल गया, लेकिन जानकारों का कहना है कि उस संकट के बाद अमरीकी अर्थव्यवस्था कमजोर जरूर हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि दुनिया और महत्वपूर्ण संस्थाओं पर 'पैनी' नजर रखने वाली रेटिंग एजेंसियों की भूमिका इस संकट के पहले और इसके दौरान ही नहीं, उसके बाद भी अत्यंत पंगु और संदेहास्पद बनी रही। मार्च के दूसरे सप्ताह में अमरीकी टैक स्टार्टअप की फंडिंग करने वाला सिलिकॉन वैली बैंक अचानक बंद हो गया और उसका अधिग्रहण अमरीकी सरकार ने कर लिया। जानकारों का मानना है कि सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 'लेहमन ब्रदर्स' के डूबने सरीखा है। लेकिन 2023 में फिर से सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के साथ ही अमरीकी वित्तीय संकट फिर से गहराने लगा है। उधर अमरीका में बढ़ती ब्याज दरों के चलते अमरीकी सरकार समर्थित मोर्टगेज प्रतिभूतियां और यहां तक कि अमरीकी ट्रेजरी बिल जो अत्यंत सुरक्षित माने जाते थे, उनकी कीमत में भी नाटकीय ढंग से गिरावट आई। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद 167 साल पुराना स्विटजरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और वैश्विक इतिहास में सबसे अधिक प्रभावशाली बैंक 'क्रेडिट सूशे' स्विटजरलैंड के सबसे बड़े बैंक 'यूबीएस' के हाथों बिक गया। जब इस बैंक से पिछले हफ्ते जमाकर्ताओं द्वारा 10 अरब डालर निकाल लिए गए तो स्विटजरलैंड सरकार ने आनन-फानन में यूबीएस द्वारा 'क्रेडिट सूशे' को खरीदने को कहा है। लेकिन इतिहास ने फिर एक बार अपने को दोहराया है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियां एक बार फिर निवेशकों को जोखिम के बारे में आगाह करने में पूरी तरह से असफल रही हैं। यदि हम देखें तो 8 मार्च, जिस दिन सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, से पहले, मूडीज ने इस पर ए-3 की रेटिंग बनाए रखी, जो इसके पैमाने पर सातवीं उच्चतम रेटिंग है। और उससे ज्यादा दिलचस्प बात यह रही कि उस दिन भी मूडीज ने उसे मात्र एक पायदान नीचे करते हुए बीएए-1 तक ही गिराया था। गौरतलब है कि ए-3 हो या बीएए-1, दोनों रेटिंग 'जंक' के पास भी नहीं और निवेशकों को रत्ती भर भी आगाह नहीं करती कि इस संस्था में निवेश हेतु कोई जोखिम है। यही बात 'क्रेडिट सूशे' के संबंध में भी लागू होती है। 'क्रेडिट सूशे' की वेबसाइट पर ही लिखा है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग 20 मार्च तक बरकरार रही। यह बात अलग है कि 'क्रेडिट सूशे' के डूबने के बाद रेटिंग को थोड़ा गिराया गया है। लेकिन यह बात उजागर हो चुकी है कि रेटिंग एजेंसियां निवेशकों को समय पर चेतावनी देने में बुरी तरह से असफल रही हैं। दुनिया में तीन प्रमुख रेटिंग एजेंसियों- स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच- की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज का मुख्यालय अमेरिका में है, जबकि फिच का मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में है। वे दुनिया भर के देशों और वित्तीय संस्थानों की रेटिंग करती हैं।

उनकी रेटिंग के आधार पर इन देशों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थानों पर लोगों का भरोसा भी इन्हीं रेटिंग्स पर निर्भर करता है। जबकि ये एजेंसियां दुनिया भर के संस्थानों और देशों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करती हैं, वे स्वयं संदेह के घेरे में हैं। यही एजेंसियां जो अमरीका और यूरोप के मुल्कों पर संकट के बावजूद कुंभकर्णीय निद्रा में रहती हैं, भारत जैसे देशों के बारे में जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, जिसका फायदा फिर उन्हीं के आका देशों को ही होता है। भारत जैसे देशों पर इतनी तल्खी और अमरीकी और यूरोपीय देशों पर मेहरबानी इन एजेंसियों पर सवालिया निशान लगाती है।

इनसाइड

अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद के बीच एनएसई का बड़ा बयान, कहा- हमारी सभी निगरानी कार्रवाई पारदर्शी

नई दिल्ली। एनएसई की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'आवेदन की अवधि के साथ सटीक मापदंड सार्वजनिक डोमेन में रहे हैं और लगातार लागू किए गए हैं।' उन्होंने कहा, 'एक्सचेंजों में आम बात है कि ये नियम स्वतः लागू होते हैं और इनपर किसी भी मानवीय दखल की गुंजाइश नहीं है। साथ ही ये नियम और समीक्षा अवधि भी बाजार के लिए पूर्व-घोषित होते हैं।' अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपनी निगरानी कार्रवाइयों के बारे में एक बयान जारी किया। देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज ने जोर देकर कहा कि सभी व्यक्तिगत शेयरों पर इसका निगरानी तंत्र पूरी तरह से पारदर्शी और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त है। एनएसई ने रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि अतिरिक्त निगरानी उपायों (एएसएम) और अन्य व्यापारिक गतिविधि-आधारित विशिष्ट नियमों जैसे मूल्य बैंड, व्यापार के लिए व्यापार (टी 2 टी) और अन्य के तहत स्टॉक्स को जोड़ने और बाहर करने की प्रक्रिया उन मापदंडों पर आधारित है जो मूल्य अस्थिरता, मात्रा, बाजार पूंजीकरण, ग्राहक एकाग्रता और तरलता मापदंडों पर संचालित होते हैं। एनएसई की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'आवेदन की अवधि के साथ सटीक मापदंड सार्वजनिक डोमेन में रहे हैं और लगातार लागू किए गए हैं।' उन्होंने कहा, 'एक्सचेंजों में आम बात है कि ये नियम स्वतः लागू होते हैं और इनपर किसी भी मानवीय दखल की गुंजाइश नहीं है। साथ ही ये नियम और समीक्षा अवधि भी बाजार के लिए पूर्व-घोषित होते हैं।'

दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है एनएसई

दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का यह बयान अदाणी समूह के तीन शेयरों को एएसएम तंत्र से हटाए जाने के दो दिन बाद आया है। इसमें अदाणी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और नई दिल्ली टेलीविजन (एनडीटीवी) के शेयर शामिल हैं। एएसएम सेबी और एक्सचेंजों की एक पहल है जिसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों को अल्पकालिक या दीर्घकालिक ढांचे में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरी ओर, स्टॉक एक्सचेंजों के अनुसार अदाणी समूह के दो शेयरों को सोमवार, 20 मार्च, 2023 से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी उपायों (एएसएम) के पहले चरण में रखा जाएगा। बीएसई और एनएसई ने अपने परिपत्रों में कहा कि दोनों प्रतिभूतियों को 20 मार्च से दीर्घकालिक एएसएम फ्रेमवर्क में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

उच्च अस्थिरता के कारण अदाणी समूह के शेयरों को रखा गया था एएसएम ढांचे के तहत

हालांकि एनएसई ने अपने बयान में किसी खास समूह या कंपनी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उच्च अस्थिरता के बीच निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक्सचेंजों की ओर से शेयरों को अतिरिक्त निगरानी ढांचे के तहत रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उच्च अस्थिरता के कारण अदाणी समूह के शेयरों को एएसएम ढांचे के तहत रखा गया है।

पायलटों की कमी के कारण एयर इंडिया का बड़ा फैसला, कुछ रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से घटेंगी

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले महीने एयर इंडिय ने एयरबस और बोइंग को 470 विमानों का ऑर्डर देने की घोषणा की थी, जिसमें 70 बड़े आकार के विमान शामिल थे। इनमें से 250 एयरबस और 220 बोइंग विमान होंगे। इनमें से अतिरिक्त 370 विमान खरीदने का भी विकल्प है।

नई दिल्ली। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैम्पबेल विल्सन ने सोमवार को कहा कि विमानन कंपनी चालक दल की कमी के कारण कुछ अमेरिकी मार्गों पर अस्थायी अवधि के लिए उड़ानों की संख्या कम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एयरलाइन के पास अगले तीन महीने में बोइंग 777 विमानों के लिए 100 पायलट होंगे क्योंकि उन्हें 'सक्रिय' किया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग 1,400 केबिन क्रू प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हाल के महीनों में चालक दल की कमी के कारण लंबी दूरी की कुछ उड़ानों के प्रभावित होने की घटनाएं सामने आई हैं। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी विल्सन ने कहा है कि चालक दल की कमी के कारण कुछ अमेरिकी मार्गों पर फ्लाइट्स की संख्या कम की गई हैं। एयरलाइन में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं, जिनमें उड़ान और गैर-उड़ान कर्मचारी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ₹बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन अब सिकुड़ के बाद और बढ़ रही है।₹ एयर इंडिया सीईओ ने राष्ट्रीय राजधानी में सीएपीए इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित कर कर रहे थे। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ घाटे में चल रही एयर इंडिया और एआईएटीएसएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। एयर इंडिया ने पांच साल की अवधि में बदलाव के लिए Vihaan.AI के तहत एक रोड मैप तैयार किया है और अपने पूरे बड़े बेड़े के अंदरूनी हिस्सों के नवीनीकरण के लिए 400 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता सहित कई उपाय किए हैं।

पिछले महीने एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 470 विमानों का ऑर्डर देने की घोषणा की थी, जिसमें 70 बड़े आकार के विमान शामिल थे। इनमें से 250 एयरबस और 220 बोइंग विमान होंगे। दोनों विमान निर्माताओं से अतिरिक्त 370 विमान खरीदने का भी विकल्प है। इसके अलावा एयर एशिया इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय और विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय शुरू किया गया है।

1400 रुपये मजबूत होकर सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, चांदी भी 1860 रुपये मजबूत

दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव 60,100 रुपये रहा इसमें 1400 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दिखी। विदेशी बाजारों में सोना और चांदी दोनों तेजी के साथ क्रमशः 2,005 डॉलर प्रति औंस और 22.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करते दिखे।

नई दिल्ली। मजबूत वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 1,400 रुपये की तेजी के साथ 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 1,860 रुपये की तेजी के साथ 69,340 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

वैश्विक बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतें बढ़ीं

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी के अनुसार, ''दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव 60,100 रुपये रहा इसमें 1400 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दिखी। विदेशी बाजारों में सोना और चांदी दोनों तेजी के साथ क्रमशः 2,005 डॉलर प्रति औंस और 22.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करते दिखे।

वैश्विक सर्राफा बाजार में तीन साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी दिखी

गांधी ने कहा कि एशियाई बाजार के कारोबारी घंटों में कॉमेक्स सोने की कीमतों में तेजी आई और यह 55 सप्ताह के उच्च स्तर 2,005 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (जिंस शोध) नवनीत दमानी ने कहा, ''बैंकिंग संकट की लहर ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया और सर्राफा में तीन साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी नजर आई।

यूबीएस से डील के बावजूद क्रेडिट सुइस के शेयर 62% तक टूटे, UBS भी 16 प्रतिशत फिसला

क्रेडिट सुइस उन 30 वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिन्हें विश्व स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों को इसके विफल होने से मंदी की आंशका सता रही है।

नई दिल्ली। यूबीएस समूह की ओर से संकटग्रस्त क्रेडिट सुइस ग्रुप के राज्य समर्थित अधिग्रहण पर मुहर लगाने के बाद सोमवार को बैंक के शेयरों और बॉन्डों में बड़ी गिरवट दर्ज की गई। स्विस नियामकों की ओर से रविवार को तैयार पैकेज के तहत यूबीएस ग्रुप ने 167 साल पुराने क्रेडिट सुइस ग्रुप के लिए 3.24 अरब स्विस फ्रैंक का भुगतान करेगा और 5.4 अरब डॉलर के नुकसान का वहन करेगा।

क्रेडिट सुइस के शेयर सोमवार को प्रीमार्केट ट्रेड में 62 प्रतिशत गिरकर नए निचले स्तर पर आ गए जबकि यूबीएस के शेयरों में 7.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दोनों बैंकों के शेयरों में एशियाई वित्तीय बाजारों में भारी बिकवाली के बाद दर्ज की गई है। इससे बैंकिंग संकट को रोकने के लिए उठाए गए आधिकारिक प्रयासों के बाद उत्पन्न निवेशकों का आशावादी रुझान जल्द ही समाप्त हो गया। बाजार खुलने के बाद यूबीएस के शेयरों में शुरुआती कारोबार में 16 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई जो सितंबर 2008 के बाद से सबसे अधिक है।

स्विस अधिकारियों ने यूबीएस से अपने छोटे प्रतिद्वंद्वी को लेने का आग्रह किया था। इससे पहले क्रेडिट सुइस के लिए 50 बिलियन फ्रैंक (54 बिलियन डॉलर) तक उधार लेने की योजना निवेशकों और बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त करने में विफल रही। बता दें कि अमेरिका में दो बैंकों की विफलता के बाद क्रेडिट सुइस और अन्य बैंकों के शेयरों में गिरावट आई और अन्य संभावित अस्थिर वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर भी सवाल उठने लगे।

दुनिया के 30 प्रमुख वित्तीय संस्थानों में एक है क्रेडिट सुइस

क्रेडिट सुइस उन 30 वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिन्हें विश्व स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों को इसके विफल होने से मंदी की आंशका सता रही है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट ने रविवार रात घोषणा करते हुए कहा कि यह समझौता वैश्विक बाजार की स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम है। क्रेडिट सुइस के अनियंत्रित पतन से पूरी दुनिया की वित्तीय प्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड की कार्यकारी शाखा एक सात सदस्यीय शासी निकाय है, इसमें बर्सेट शामिल हैं। उन्होंने एक एक आपातकालीन अध्यादेश पारित किया है जिसमें शेयरधारक की मंजूरी के बिना विलय की अनुमति दी गई।

हालांकि स्थिरता बहाल करने के लिए नियामकों के ओर से किए जा रहे अथक प्रयासों के बावजूद बाजार परेशान है। वैश्विक शेयर बाजारों में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखी। हांगकांग का मुख्य सूचकांक 3% से अधिक फिसल गया। फ्रैंकफर्ट और पेरिस में बाजार बेंचमार्क 1% से अधिक नीचे खुले। शंघाई, टोक्यो, सिडनी और भारतीय बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर भी 1% नीचे फिसला। तेल की कीमतों में 2 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। क्रेडिट सुइस के चेयरमैन एक्सेल लेहमैन ने यूबीएस को संस्थान की बिक्री के कदम को एक स्पष्ट टर्निंग प्वाइंट बताया।

लीमैन ने कहा, ₹यह क्रेडिट सुइस के लिए, स्विट्जरलैंड के लिए और वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक, दुखद और बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है,₹ लेहमैन ने कहा कि अब ध्यान भविष्य पर और क्रेडिट सुइस के 50,000 कर्मचारियों पर है इनमें से 17,000 स्विट्जरलैंड में हैं।

केरल के दो कारोबारियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी, आयकर विभाग की कार्रवाई

केरल। आयकर विभाग ने सोमवार को कई राज्यों में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी उनके खिलाफ की गई है, जिनका संबंध कथित तौर पर केरल के दो प्रभावशाली व्यवसायियों से है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, केरल, तमिलनाडु, बेंगलुरु और मुंबई में उनके कथित रियल एस्टेट सौदे का पता लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है। जिन कारोबारियों की जांच की जा रही है, उनमें से एक कथित तौर पर राज्य के कुछ शीर्ष नेताओं से जुड़ा हुआ है। छापेमारी आज सुबह करीब साढ़े दस बजे शुरू हुई।

निचले स्तरों से 554 अंक संभला बाजार, सेंसेक्स 361 अंक नीचे; निफ्टी 17000 से फिसला

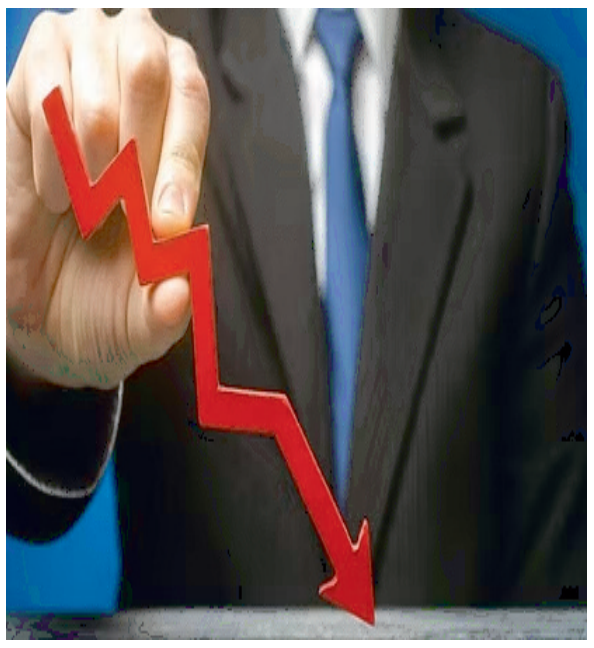

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 360.95 (-0.62%) अंकों की गिरावट के साथ 57,628.95 अंकों के लेवल पर जबकि निफ्टी 111.65 (-0.65%) अंक फिसलकर 16,988.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। सोमवार के कारोबारी सेशन के दौरान बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी और यहां से सेंसेक्स लगभग 554 अंक संभला।दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 57,084 अंकों के लेवल तक फिसल गया था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। इस दौरान बजाज फिनसर्व के शेयरों में चार प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग, मेटल और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी।

बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार के दिन निवेशकों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 255.64 लाख करोड़ रुपये हो गया। बीते 17 मार्च को यह 257.52 लाख करोड़ रुपये था।

कमजोर वैश्विक संकेतों के बाद फिसला बाजार सेंसेक्स 398 अंक टूटा, निफ्टी 17000 से नीचे

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स बेंचमार्क 398.18 अंक फिसलकर 57,527.10 अंकों के लेवल पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बेंचमार्क 131.85 अंक टूटकर 16,945.05 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान बजाज ट्विन्स के शेयरों में चार प्रतिशत तक की गिरावट आई।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स के 30 शेयरों का हाल

निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर शेयर्स

हफ्तेभर में निवेशकों को तीन लाख करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

बीते एक हफ्ते के दौरान शेयर बाजार में निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले हफ्ते शुक्रवार को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 257.52 लाख करोड़ रुपए था, वह इस हफ्ते 254.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

 # वेदांता लिमिटेड ने विंडफॉल टैक्स के के विरोध में उठाया ये कदम

खनन क्षेत्र के दिग्गज अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड ने नौ महीने पुराने विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित कर) के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए तेल और गैस क्षेत्रों से सरकार को होने वाले लाभ के हिस्से से करीब 9.91 करोड़ डॉलर की राशि रोक दी है। भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। सरकार अपने इस कदम से ऊर्जा कंपनियों के सुपर सामान्य मुनाफे पर कर लगाने वाले देशों में शामिल हो गया था। लेकिन स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) लगाने के फैसले का उत्पादक कंपनियों ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसे उस अनुबंध का उल्लंघन मानते हैं जो राजकोषीय स्थिरता प्रदान करता है। एसएईडी (Special Additional Excise Duty) शुरू में 23,250 रुपये प्रति टन (40 डॉलर प्रति बैरल) था लेकिन सरकार ने आगे चलकर इसमें पाक्षिक संशोधन करते हुए घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया था।

पोलैंड के राजदूत एडम ने कहा- भारत फिर मिलेंगे, पढ़िए हिंदी में क्या-क्या बोले

नई दिल्ली। एडम ने कहा कि भारत से 26 साल पुराना मेरा रिश्ता है। मैं 1997 में पहली बार एक टूरिस्ट की तरह भारत आया था। मैंने भारत में काफी जगह घूमी थीं। तभी मुझे भारत से प्यार हो गया था। भारत में दिल्ली में कार्यरत पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोव्सकी ने कहा कि भारत फिर मिलेंगे। एडम अब दक्षिण अफ्रीका में अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। भारत छोड़ने से पहले उन्होंने हिंदी में बात करते हुए कहा कि भारत फिर मिलेंगे। एडम ने कहा कि भारत से 26 साल पुराना मेरा रिश्ता है। मैं 1997 में पहली बार एक टूरिस्ट की तरह भारत आया था। मैंने भारत में काफी जगह घूमी थीं। तभी मुझे भारत से प्यार हो गया था। मुझे हिंदी भाषा पसंद आई, मैंने हिंदी सीखना शुरू किया। भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति में रुचि विकसित की। मेहनत करते-करते मैं आज भारतीय राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ बन गया।

पोलैंड भी करता है भारत की मदद

पोलैंड में कुछ स्थानों का नाम महाराजाओं के नाम पर रखा गया है। क्योंकि, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत ने 6000-7000 पोलैंड शरणार्थियों को शरण दी थी। पोलैंड भी भारत की मदद करता है। यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान लगभग 6000 भारतीय छात्रों को पोलैंड ने निकालने में मदद की। अब भारत और पोलैंड अधिक जुड़े हुए हैं। अधिक आर्थिक सहयोग और लोगों से लोगों के संबंध बढ़े हैं।

पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश रद्द
अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपये का जुर्माना

फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों?

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल, मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

इस आदेश को एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाए। केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। कोर्ट ने कह कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा?

अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता में शीर्ष पर रही आईटीबीपी, एनएसजी समेत 24 टीमों ने लिया था हिस्सा

नई दिल्ली। विशिष्ट पर्वत-प्रशिक्षित बल आईटीबीपी ने पहली बार यह प्रतियोगिता जीती है। 11-दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 21 मार्च को हुआ था, जबकि 31 मार्च को इसका समापन समारोह मानेसर में हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता देश के पुलिस बलों के बीच सबसे कठिन पेशेवर प्रतियोगिताओं में से एक है...

80 के दशक में जटिल सुरक्षा चुनौतियों के आलोक में आईटीबीपी के जांबाजों ने 1982 के एशियाई खेलों की सुरक्षा के लिए कमांडो प्रदान किए थे। उसके बाद 1983 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) और नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) 1983 की बैठक हुई थी, उसमें भी बल के कमांडो ने अचूक सुरक्षा प्रदान की थी। अब इसी बल ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता (एआईपीसीसी) 2023 का 13वां संस्करण जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की 24 शीर्ष कमांडो टीमों ने भाग लिया था। विशिष्ट पर्वत-प्रशिक्षित बल आईटीबीपी ने पहली बार यह प्रतियोगिता जीती है। 11-दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 21 मार्च को हुआ था, जबकि 31 मार्च को इसका समापन समारोह मानेसर में हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता देश के पुलिस बलों के बीच सबसे कठिन पेशेवर प्रतियोगिताओं में से एक है। प्रतियोगिता ट्रॉफी के अलावा, आईटीबीपी टीम ने फायरिंग में सर्वश्रेष्ठ और रणनीति में सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी भी जीती। प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड (एआईपीएससीबी) द्वारा किया गया था। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को पुलिस बलों की शारीरिक फिटनेस, सामरिक कौशल, मानसिक मजबूती, निशानेबाजी कौशल, नेतृत्व गुणों और श्रेष्ठ संगठन भावना पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस कमांडो टीम का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रतियोगिता का यह संस्करण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे दो संस्करणों (11वें और 12वें) के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, जो कि कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं किए गए थे।

वर्ष 2009 में शुरू हुई अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का पहला संस्करण मध्यप्रदेश के टेकनपुर में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता को देश के पुलिस बलों के बीच शीर्ष पेशेवर प्रतियोगिता माना जाता है। 1962 के बाद से सबसे कठिन जलवायु और इलाके की परिस्थितियों में भारत-चीन सीमाओं की रक्षा करने के अलावा, आईटीबीपी का देश में बेहतरीन कमांडो तैयार करने का एक विशिष्ट इतिहास रहा है। इसी वजह से 80 के दशक में जब जटिल सुरक्षा चुनौतियां रही थीं, तब एशियाई खेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी कमांडो ने संभाली थी। इसके बाद 1983 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) और नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) 1983 की बैठक के दौरान भी बल के कमांडो ने सुरक्षा प्रदान की थी।

इसके अलावा फोर्स ने 2005 से 2008 तक अफगानिस्तान में डेलाराम-जरंज परियोजना को सुरक्षित करने के लिए अपनी कमांडो इकाइयां भेजी थीं। बल ने 2005 से 2019 तक भारतीय-गठित पुलिस यूनिट-1 (आईएनडी एफपीयू-1) के लिए अपने कमांडो को अफ्रीका के कांगो में भी भेजा था। आईटीबीपी कमांडो ने शीर्ष पेशेवर कौशल के साथ अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की रक्षा की है। बल ने गत वर्षों में वहां कई आतंकवादी हमलों को विफल किया है।

दिवंगत मंत्री नब किशोर दास की बेटी दीपाली होंगी बीजद की उम्मीदवार, जानें उनके बारे में

बीजू जनता दल (BJD) ने झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ओडिशा के दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की बेटी दीपाली दास के नाम की घोषणा की।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का एलान होने के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजद ने वहां से अपने उम्मीदवार के नाम का एलान कर दिया है। बीजद ने झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र से दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की बेटी दीपाली दास को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की इसी साल जनवरी में एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

ओडिशा के दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास के निधन से रिक्त हुई झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा बीते बुधवार को चुनाव आयोग ने की थी। चुनाव आयोग ने झारसुगुड़ा विधानसभा सीट के साथ ही पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश की छानबे और स्वार विधानसभा सीट और मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। इन सीटों पर 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे।

जानकारी के मुताबिक, बीजू जनता दल (BJD) ने झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ओडिशा के दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की बेटी दीपाली दास के नाम की घोषणा की।

जानें कौन हैं दीपाली दास

गौरतलब है कि ओडिशा के दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास वहां से सबसे धनी मंत्रियों में गिने जाते थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। मंत्री की बेटी अक्सर उनके साथ राजनीतिक मंचो पर दिखती थी। बीते साल अक्टूबर 2022 में नब किशोर दास ने अपनी बेटी दीपाली दास को झारसुगुड़ा के नेता के रूप में घोषित भी किया था।

आम आदमी पार्टी ने जारी की 60 उम्मीदवारों की दूसरी सूची; पहले किया था 80 नामों का एलान

कर्नाटक पुलिस ने को कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा और उनके बेटे व कांग्रेस के पूर्व विधायक शमनूर मल्लिकार्जुन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन पर मतदाताओं को उपहार बांटने का आरोप है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए 60 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले पार्टी ने 20 मार्च को 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। आप ने राज्य के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के वकील बृजेश कलप्पा चिकपेट से चुनाव लड़ेंगे। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के पूर्व अधिकारी के मथाई (शांति नगर), बी.टी. नागन्ना (राजाजीनगर), मोहन दसारी (सी वी रमन नगर), शांतला दामले (महालक्ष्मी लेआउट से) और पद्मनाभनगर से अजय गौड़ा चुनाव लड़ेंगे।

येदियुरप्पा नहीं लड़ेंगे चुनाव

पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने साफ कर दिया कि इस बार वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसकी घोषणा की। एक प्रेसवार्ता में येदियुरप्पा ने कहा, मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सीएम पद से भी इसलिए इस्तीफा दिया था, क्योंकि मैं पहले ही 80 साल की उम्र पार कर चुका हूं।

उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं 80 साल से अधिक हो गया हूं, मैं इस बार ही नहीं बल्कि अगली बार भी राज्य में घूमूंगा। येदियुरप्पा ने आगे कहा, हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई मेल नहीं है। मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनका नेता कौन है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के समान हो सकते हैं।

मतदाताओं को उपहार बांटने में कांग्रेस विधायक और बेटे पर एफआईआर

कर्नाटक पुलिस ने को कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा और उनके बेटे व कांग्रेस के पूर्व विधायक शमनूर मल्लिकार्जुन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन पर मतदाताओं को उपहार बांटने का आरोप है।

दावणगेरे जिले के केटीजे नगर पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया। दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं ने मुफ्त उपहार बांटने पर शमनूर शिवशंकरप्पा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। महिलाओं ने बताया कि दावणगेरे में ग्रामीणों ने विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा और उनके बेटे व कांग्रेस नेता शमनूर मल्लिकार्जुन की ओर से वितरित उपहारों को आग के हवाले कर दिया।

चुनावी कदाचार में जद (एस) विधायक अयोग्य करार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के तुमकुरु ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जनता दल (सेकुलर) के विधायक डीसी गौरीशंकर स्वामी को चुनावी कदाचार के एक मामले में अयोग्य ठहराया। हालांकि, अदालत ने अयोग्यता को एक महीने के लिए निलंबित करते हुए स्वामी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की अनुमति दी। हारने वाले भाजपा प्रत्याशी बी सुरेश गौड़ा ने आरोप लगाया था कि 2018 के चुनाव में मतदाताओं को फर्जी बीमा बांड बांटकर स्वामी ने कथित तौर पर चुनावी गड़बड़ी की।

ट्रांसजेंडर महिला को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने का अधिकार, उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग परिवर्तन के बाद उसी लिंग का माना जाएगा, जो उसके द्वारा चुना गया है।

मुंबई। घरेलू हिंसा कानून के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद महिला बन गई है, वह भी घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने का अधिकार रखती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को कायम रखा है और व्यक्ति को अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। बता दें कि महिला, पहले पुरुष थी और लिंग परिवर्तन सर्जरी कराकर महिला बनी।

हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी

जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल बेंच वाली पीठ ने 16 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि 'महिला' शब्द सिर्फ महिला और पुरुष के रूप में सीमित नहीं है बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, जो अपना लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन चुके हैं। जस्टिस बोरकर ने रेखांकित किया कि घरेलू हिंसा कानून की धारा 2(एफ) के तहत घरेलू रिश्ते लैंगिक तौर पर तटस्थ होते हैं। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग परिवर्तन के बाद उसी लिंग का माना जाएगा, जो उसके द्वारा चुना गया है। पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून का उद्देश्य घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

क्या है मामला

दरअसल अक्टूबर 2021 में एक सत्र अदालत ने व्यक्ति को उससे अलग रह रही पत्नी को गुजारे भत्ते के तौर पर 12 हजार रुपए महीने का भुगतान करने का निर्देश

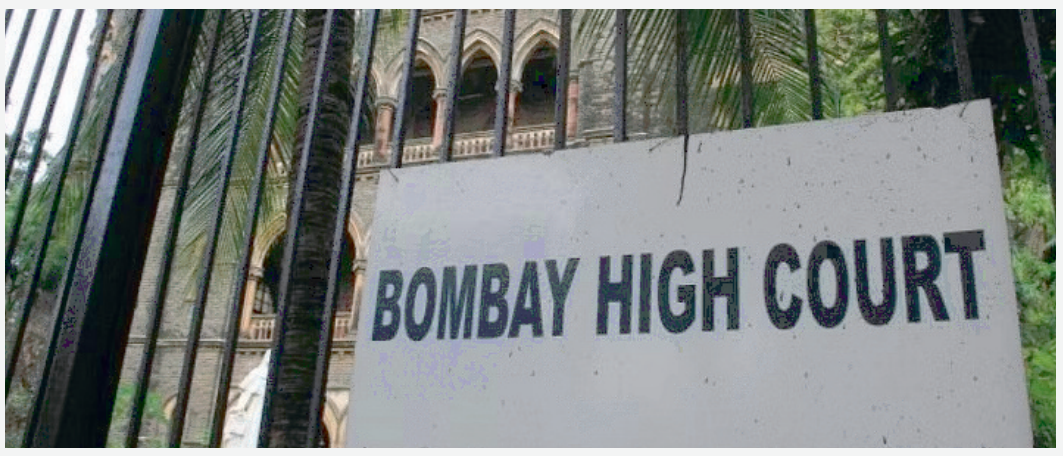

दिया था। व्यक्ति की पत्नी एक ट्रांसजेंडर है और लिंग परिवर्तन सर्जरी कराकर महिला बनी है। महिला ने घरेलू हिंसा कानून के तहत अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। महिला का कहना था कि वह 2016 में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गई थी, ऐसे में वह घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने की अधिकारी है।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि उसकी पत्नी ट्रांसजेंडर है, इसलिए वह घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने की अधिकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर उक्त टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने और बकाया को चार हफ्ते में देने का निर्देश दिया है।

सीएम पी विजयन के खिलाफ आपदा राहत कोष मामला, केरल लोकायुक्त की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष मामला लोकायुक्त की बड़ी पीठ के पास भेजा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में कथित हेराफेरी के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कई मंत्रियों पर आरोप है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का दुरुपयोग किया गया। इस मामले की जांच के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार पर रोक के लिए गठित लोकायुक्त के पास जाने का निर्देश दिया। इसके बाद लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू की। आरोप है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को पक्षपातपूर्ण तरीके से बांटा गया। लाभार्थियों में सीपीआई (एम) के विधायक के परिवार के लोग शामिल हैं।

> मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का मामला सुनवाई के लिए लोकायुक्त की बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है।

साथ ही केरल पुलिस के एक अफसर के परिजनों को भी लाभ दिया गया। दोनों का निधन हो चुका है और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया। साल 2019 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को लोकायुक्त ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई लेकिन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत उनके परिवारों को वित्तीय सहायता नहीं दी गई। साथ ही नियमों के मुताबिक जिन लोगों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, उन्हें भी मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती लेकिन मंत्रीपरिषद ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023